वर्ष : 17 ❖ अंक : 184 ❖ पृष्ठ : 08 ❖ मूल्य : ₹ 3.00 ❖ आरएनआई सं. SIKHIN/2006/17890 ❖ www.anugamini.com

सिक्किम से प्रकाशित प्रथम हिन्दी दैनिक

अनुगामिनी

गंगटोक
गुरुवार, 09 फरवरी 2023

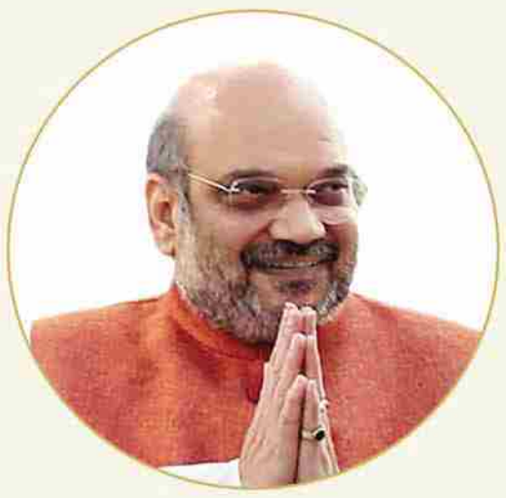

कृतज्ञता

सिक्किमी नेपाली पर युगों से लगे विदेशी के कलंक को सदा के लिए मिटाने वाला महान कार्य करने के लिए सम्पूर्ण सिक्किमी जनता की ओर से हम हमारे देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, माननीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय कानून मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग जी को बहुत सारा धन्यवाद देते हैं।

– सिक्किम की जनता

राज्यपाल के भाषण के बीच बीजेपी विधायकों ने किया वॉकआउट, कहा- गवर्नर ने पढ़ा राज्य सरकार का भाषण

कोलकाता, 08 फरवरी (एजेन्सी)। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने विधानसभा में अपने उद्घाटन भाषण में बुधवार को केंद्र सरकार से गरीब लोगों के लिए राज्य को धन जारी करने का आग्रह किया। उनका भाषण ममता बनर्जी सरकार और सत्तारूढ़ टीएमसी के केंद्र पर राज्य को धन जारी न करने के आरोप लगाने के बाद आया है।

राज्यपाल ने विधानसभा में कहा कि मनरेगा, ग्रामीण आवास और ग्रामीणों सड़कों के क्षेत्र में राज्य राज्य बेहतर कर सकता था। 2021-22 में पश्चिम बंगाल इन क्षेत्रों में नंबर एक रहा है। लेकिन इस वर्ष राज्य को अभी तक धन प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि केंद्र गरीब लोगों के हित में जल्द ही धन जारी करेगा और पश्चिम बंगाल जल्द से जल्द मनरेगा, ग्रामीण आवास और ग्रामीण सड़कों में नंबर एक स्थान पर बना रहेगा।

नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि राज्यपाल ने सरकार द्वारा तैयार किया गया भाषण पढ़ा था। अधिकारी ने संवाददाताओं से कहा, राज्यपाल ने सदन में जो कुछ भी कहा है वह सिर्फ एक नियम है क्योंकि उन्हें राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए भाषण को पढ़ना है।

अभिभाषण के दौरान उन्होंने जो कहा उससे हम सहमत नहीं हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, हमने विरोध तब किया जब राज्यपाल ने यह कहना शुरू किया कि राज्य में कानून व्यवस्था शांतिपूर्ण है। उन्होंने कहा, राज्यपाल की इस बात को स्वीकार करना संभव नहीं है। जिस तरह से राज्यपाल केंद्र सरकार के खिलाफ पढ़ रहे थे, हमने उसका विरोध किया। राज्यपाल को भाषण पढ़ने से पहले तथ्यों की जांच करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि राज्यपाल उचित कदम उठाएंगे, क्योंकि वह गुमराह हैं। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, सीएम ममता बनर्जी) रोहिंग्याओं की रक्षा कर रही हैं, जबकि अमित शाह रोहिंग्याओं के खिलाफ लड़ रहे हैं।

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के विधानसभा में संबोधन के बीच भाजपा विधायकों ने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सदन से बहिर्गमन किया।

अगले सप्ताह राज्य के बजट से पहले बोस ने सदन में अपना संबोधन शुरू करने के कुछ ही मिनटों के भीतर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। अधिकारी ने कहा, बंगाल की सरकार भ्रष्ट सरकारों में से एक है। हमने वाकआउट किया क्योंकि भाषण में भ्रष्टाचार के मामलों और टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी का कोई जिक्र नहीं है। टीएमसी नेता निर्मल घोष ने भाजपा पर विधानसभा की कार्यवाही में बाधा डालने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

संसद में संग्राम, खड़गे बोले- कैसे अदाणी की संपत्ति 50 हजार करोड़ से बढ़कर लाखों करोड़ हो गई

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने फिर की जेपीसी की मांग

नई दिल्ली, 08 फरवरी (एजेन्सी)। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को राज्यसभा में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. मल्लिकार्जुन खड़गे ने अदाणी के मुद्दे पर भी हमला बोला। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि क्या जादू हुआ कि एक कारोबारी की संपत्ति इतनी बढ़ गई।

बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में मौजूद रहे। इस दौरान विपक्ष की ओर से चर्चा शुरू करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद मलिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2014 में एक उद्योगपति की संपत्ति 50 हजार करोड़ रुपए थी लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि दो ही साल में इस उद्योगपति की संपत्ति लाखों करोड़ रूपए बढ़ गई। खड़गे ने अदानी का नाम लिए बिना कहा कि पीएम के एक दोस्त की संपत्ति अचानक कई गुना बढ़ गई। इसके जवाब में तुरंत नेता सदन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह बिना आधार के आरोप लगाए जा रहे हैं।

पीयूष गोयल ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि यह अपने नेता की संपत्ति देख लें कि 2014 में कितनी थी और आज वह संपत्ति कितनी बढ़ गई है।

कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस उद्योगपति को सरकार से प्रोत्साहन व समर्थन मिला है, सरकारी बैंकों से उसे काफी रकम मिली है। खड़गे ने कहा गुजरात में 31 पैसे का कर्ज बकाया होने पर एक किसान को 'नो ऑब्जेक्शन' सर्टिफिकेट नहीं मिला, लेकिन उद्योगपतियों के हजारों करोड़ रुपए माफ किए गए। एयरपोर्ट, कोल, रोड, सीमेंट एक व्यक्ति को मिल रहा है और उसको यह खरीदने के लिए पैसा भी सरकारी बैंकों से उपलब्ध हो रहा है।

खड़गे ने कहा कि मैं राष्ट्रपति को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद देता हूं। मुझे ऐसी उम्मीद थी कि राष्ट्रपति दबाव बनाकर समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए अपने अभिभाषण में कुछ बातें शामिल करवाएंगी लेकिन मुझे निराशा हुई। खड़गे ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में नीतियों की चर्चा होती है कि किन नीतियों के आधार पर हम, कैसे हम देश को चलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने अपनी सरकार की कुछ उपलब्धियां बताई और बाकी पिछली सरकारों की खामियां गिनाई।

खड़गे ने कांग्रेस के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश के विकास में बुनियाद के पत्थर डाले हैं लेकिन आज वह पत्थर नहीं दिखाए जा रहे बल्कि उन पत्थरों की बुनियाद पर बनी इमारतों को दिखाया जा रहा है।

खड़गे ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला मौसम और भी खराब आने वाला है क्योंकि हमें बात करने नहीं देते अपने मुद्दों को उठाने नहीं देते।

खड़गे ने कहा कि मैं देखता हूं सदन के भीतर और बाहर भी मंत्री और सत्ता पक्ष के सांसद नफरत की बात ज्यादा करते हैं। ये लोग ज्यादातर सांप्रदायिक और जाति की बातें करते हैं। भारत छोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली, मैं भी उसमें शामिल हुआ। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा किसी के खिलाफ नहीं है। 3600 किलोमीटर चलना और लोगो के विचार को सुनना और लोगों ने जो कहा उससे आगे के लिए मार्गदर्शन लेना यह यात्रा का उद्देश्य था।

बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद मलिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर सदन में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी (जेपीसी) जांच की मांग की। खड़गे ने कहा कि सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के लिए जेपीसी का गठन किया जाना चाहिए। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री व नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी यानी जेपीसी तब बैठती है जब कोई आरोप सिद्ध होता है। कोई रक्षा का घोटाला होता है या कांग्रेस के राज में हुए कोयला घोटाले जैसे घोटाले सामने आते हैं। जवाब में मलिकार्जुन खड़गे ने कहा सरकार ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी से क्यों भाग रही है, हमें पता नहीं लेकिन आप भागते जाओ हम पीछा करके पकड़ेंगे।

खड़गे ने सरकार से प्रश्न करते हुए कहा कि क्या आप शेड्यूल कास्ट को हिंदू नहीं समझते और यदि समझते हैं तो उसे मंदिर में क्यों नहीं जाने देते। उसे पानी क्यों नहीं लेने देते, वोट के लिए उसके घर में खाना खाने जाते हो, लेकिन उसे बराबरी नहीं देते। उन्होंने कहा कि मैं दुख के साथ कहता हूं कि मेरा दर्द यह लोग समझ नहीं सकते। उन्होंने कहा कि जो यह कठिनाई झेलता है वही इस दर्द को जानता है।

उन्होंने कहा कि देश में धर्म के नाम से, जाति के नाम से, भाषा के नाम से नफरत फैलाई जा रही है। खड़गे ने सदन में कहा कि 'नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो'। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सभी का सम्मान करना चाहिए चाहे वह गरीब हो, अमीर हो या कोई भी हो। उन्होंने कहा कि लोग नफरत फैला रहे हैं। लोगों को डरा रहे हैं, लेकिन मेरा प्रश्न प्रधानमंत्री से है कि प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं।

प्रधानमंत्री पर चुख्रपी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने तल्ख टिख्रपणी की तो इस पर सभापति ने आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि खड़गे जी यह भाषा आपके कद के अनुरूप नहीं है। इस पर मलिकार्जुन खड़गे ने अपना लंबा राजनीतिक एवं संसदीय अनुभव गिनाते हुए सभापति से कहा कि मुझे बोलने के बीच में बार-बार रोका जा रहा है, क्या अब मुझे बोलना भी आप सिखाएंगे। वहीं सभापति द्वारा खड़गे को टोके जाने के बाद कांग्रेस सांसदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि देश में 41 प्रतिशत शिक्षकों के पद खाली हैं। ऐसे में विज्ञान, गणित और अन्य विषयों के शिक्षकों की अनुपस्थिति में छात्र क्या पढ़ाई करेंगे। खड़गे ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज लोगों की स्वतंत्रता और समानता का अधिकार छीना जा रहा है।

इससे पहले राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की शुरूआत भाजपा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर ने की। उन्होंने इस दौरान मोदी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनाया, खासतौर पर ढांचागत विकास की जानकारी दी। उन्होंने सदन के सामने रखे अपने भाषण में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे, देश में बनाए गए नए एयरपोर्ट रेलवे लाइनों आदि का जिक्र किया।

सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं राहुल : रविशंकर प्रसाद

नई दिल्ली, 08 फरवरी (एजेन्सी)। भाजपा के लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को संसद में आरोप लगाया कि गांधी परिवार भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और खुद जमानत पर बाहर होने के बावजूद केंद्र सरकार पर निराधार आरोप लगा रहा है।

लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बोलते हुए, प्रसाद ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अदाणी समूह का कथित रूप से पक्ष लेने के आरोप का उल्लेख करते हुए कहा कि गांधी की टिख्रपणी झूठी और शर्मनाक थी।

प्रसाद ने कहा कि गांधी सदन को गुमराह कर रहे। गांधी ने मंगलवार को अदाणी एंटरप्राइजेज पर अमेरिका की रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने दावा किया था कि 2014 में भाजपा के सत्ता में आने के तुरंत बाद गौतम अदाणी की किस्मत चमक गई।

प्रसाद ने कहा, जो लोग जमानत पर बाहर हैं और वर्तमान में मुकदमे का सामना कर रहे हैं (नेशनल हेराल्ड मामले में) निराधार आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी इस तथ्य को पचा नहीं पा रहे हैं कि लोगों ने नरेंद्र मोदी को दो बार प्रधानमंत्री चुना और वह 2024 में फिर से आएंगे।

भाजपा सांसद ने बताया कि अदाणी समूह ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ और यहां तक कि वाम शासित केरल में भी निवेश किया है। प्रसाद ने विदेशों में अदाणी की संपत्ति के संबंध में गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों का भी खंडन करते हुए कहा कि यूपीए शासन के दौरान भी समूह ने विदेशी निवेश किया था। प्रसाद ने आगे कहा कि कांग्रेस शासन 2जी स्पेक्ट्रम, राष्ट्रमंडल खेलों के अलावा कोयला और आदर्श हाउसिंग घोटालों में भ्रष्टाचार से प्रभावित था।

राहुल का तीर सही जगह लगा है : अधीर रंजन

नई दिल्ली, 08 फरवरी (एजेन्सी)। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सदन में अपनी बात रखकर सही जगह वार किया है जिससे पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ खड़ी हो गई है।

उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि राहुल गांधी ने भाजपा को पख्रपू बना दिया है।

चौधरी ने कहा, पहली बार ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि भाजपा ने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया। क्या यह सियासी फसल उगाने के लिए हुआ? पहले राष्ट्रपति की जाति, धर्म की बात कभी नहीं हुई। हम तो प्रधानमंत्री को ओबीसी की बात नहीं करते, हम प्रधानमंत्री बोलते हैं।

उन्होने कटाक्ष करते हुए कहा, ऐसा लगता है कि सब कुछ राहुल बनाम भाजपा हो गया है। प्रधानमंत्री से पहले सारे ब्रिगेडियर को तैनात किया गया। उससे लगता है कि राहुल गांधी जी ने सही जगह वार किया। उनका तीर सही जगह लगा है। राहुल गांधी ने आपको पख्रपू बना दिया।

इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने तंज कसा, आप माननीय सांसद को पख्रपू नहीं कह सकते।

चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी की बात पर पूरे हिंदुस्तान में चर्चा हो रही है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, आपके यहां एक मुस्लिम सांसद नहीं, एक मुस्लिम मंत्री नहीं है और आपके कहते हैं कि दुनिया आपके लिए परिवार है।

कांग्रेस नेता ने चीन के साथ सीमा पर तनाव का उल्लेख करते हुए कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री रहते हुए जब चीन ने भारत पर हमला किया तो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी के आग्रह पर संसद में चर्चा हुई थी और 165 सदस्यों ने भाग लिया था।

इस अमित शाह ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, उस वक्त खामियां थीं, आज खामियां नहीं है।

चौधरी ने कहा कि सरकार को चीन के मामले पर चर्चा करनी चाहिए।

NAGALAND STATE LOTTERIES
Draw Time: 01:00 PM
DEAR TORSA MORNING
WEDNESDAY WEEKLY LOTTERY
Draw No:115 DrawDate on:08/02/23
1st Prize ₹1 Crore/- 52E 04125
(Including Super Prize Amt)
Cons. Prize ₹1000/- 04125 (REMAINING ALL SERIALS)
2nd Prize ₹9000/-
18593 27643 33580 42624 63630 69504 73961 76050 80848 88948
3rd Prize ₹450/-
1188 1500 1647 1846 2556 4463 4815 7375 8048 9387
4th Prize ₹250/-
0100 2388 3752 6184 7961 8018 8035 8354 9553 9705
5th Prize ₹120/-
0120 0194 0292 0495 0500 0538 0676 0817 1174 1297
1427 1453 1684 1814 1866 2075 2105 2205 2327 2347
2383 2579 2638 2830 2838 2870 3007 3210 3540 3541
4194 4390 4426 4465 4559 4792 4947 5006 5045 5130
5148 5211 5665 5722 5865 6152 6616 6651 6729 6751
6852 6934 6944 6971 6982 7065 7112 7152 7187 7196
7321 7393 7405 7412 7445 7459 7476 7614 7744 8001
8016 8027 8060 8084 8172 8216 8281 8359 8468 8556
8557 8746 8790 8867 9036 9285 9307 9332 9359 9382
9484 9510 9528 9530 9610 9663 9689 9807 9870 9893
ISSUED BY : THE DIRECTOR
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND
For Results, Please Visit : Www.Nagalandlotteries.Com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

NAGALAND STATE LOTTERIES
Draw Time: 06:00 PM
DEAR MERCURY WEDNESDAY
WEEKLY LOTTERY
Draw No:115 DrawDate on:08/02/23
1st Prize ₹1 Crore/- 92J 43386
(Including Super Prize Amt)
Cons. Prize ₹1000/- 43386 (REMAINING ALL SERIALS)
2nd Prize ₹9000/-
05005 05204 16111 29832 38242 38699 42424 46882 93514 99772
3rd Prize ₹450/-
0049 0200 1462 1959 4162 4722 5279 6305 6894 8971
4th Prize ₹250/-
0238 1949 2006 2140 2444 4065 8038 8965 9452 9925
5th Prize ₹120/-
0012 0120 0175 0612 0685 0768 0876 1064 1085 1100
1157 1550 1713 1743 1808 1992 2054 2121 2128 2300
2319 2436 2442 2461 2728 2773 2801 2850 2976 3059
3061 3300 3384 3444 3446 3551 3864 3870 4169 4228
4240 4562 4607 4677 4702 4782 5031 5046 5068 5135
5142 5334 5538 5607 5671 5687 5829 5950 6003 6024
6248 6303 6549 6600 6601 6808 6968 7122 7135 7215
7311 7383 7426 7442 7459 7709 7737 7764 7890 8113
8155 8211 8244 8254 8257 8484 8488 8496 8506 8592
8760 9140 9351 9352 9458 9482 9649 9861 9868 9895
ISSUED BY : THE DIRECTOR
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND
For Results, Please Visit : Www.Nagalandlotteries.Com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

NAGALAND STATE LOTTERIES
Draw Time: 08:00 PM
DEAR EAGLE EVENING
WEDNESDAY WEEKLY LOTTERY
Draw No:215 DrawDate on:08/02/23
1st Prize ₹1 Crore/- 50K 89464
(Including Super Prize Amt)
Cons. Prize ₹1000/- 89464 (REMAINING ALL SERIALS)
2nd Prize ₹9000/-
13773 15977 47341 48111 50181 54893 55827 73080 75038 85255
3rd Prize ₹450/-
0515 0958 1092 1738 4474 4614 5196 7015 7905 8934
4th Prize ₹250/-
0437 0752 2014 3427 4232 4810 4945 6774 7485 9700
5th Prize ₹120/-
0093 0118 0169 0171 0214 0393 0458 0485 0534 0707
0757 0840 1118 1120 1163 1539 1737 1938 2193 2245
2301 2338 2345 2352 2663 2674 2794 2971 3034 3136
3331 3374 3629 3705 3736 4000 4010 4172 4286 4395
4491 4524 4865 4899 5019 5185 5233 5387 5391 5446
5489 5497 5500 5537 5538 5700 5819 5998 6041 6185
6245 6448 6453 6583 6727 6754 6796 6934 6945 7084
7175 7265 7364 7587 7611 7947 8058 8123 8225 8232
8332 8350 8402 8496 8558 8634 8655 8660 8701 8806
8894 8909 9073 9512 9554 9563 9821 9843 9875 9933
ISSUED BY : THE DIRECTOR
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND
For Results, Please Visit : Www.Nagalandlotteries.Com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

GOVERNMENT OF SIKKIM
SPORTS & YOUTH AFFAIRS DEPARTMENT

No.: 692/SYA/EC/2022/811 Dated: 06.01.2023

NOTICE INVITING TENDER

Sealed tenders in percentage rates are invited on behalf of Governor of Sikkim for the work mentioned below from the APPROPRIATE CLASS of registered contactors enlisted under SPWD within the territorial jurisdiction as indicated vide Memo No.: 01/GOS/R&B/Gen/2005-06/109(A)/Planning. Dated 28/09/2021 and having experience in such works should reach the office of the Superintending Engineer, Sports & Youth Affairs Department, White Hall, Gangtok, East Sikkim a per the schedule given below.

DETAILS OF TENDER

Sl. No.	Name of Work	Cost of work put to tender (in ₹)	Earnest Money 2.5% of bid value (in ₹)	Cost of tender documents (in ₹)	Time of completion	Territorial Jurisdiction
1	2	3	4	5	6	7
1	Construction of Mini Stadium at Sadam, South Sikkim	2,50,59,796.00	6,26,495.00	30,000.00	18 months	Melli Constituency

This tender is based on the Notification 515/R&B/PWD/Secy, Dated : 12th June 2018, followed by amendment to the said notification vide Memo No.: 01/GOS/R&B/Gen/2005-06, Dated: 07/12/2020.

TIME SCHEDULE

1. Date of submission of application with Challan/Bank Receipt for issue of tender document (excluding tender form) : 15/02/2023 to 22/02/2023 from 10:00 AM to 3:00 PM
2. Date of issue of tender form on submission of TDR (as earnest money) : 23/02/2023 to 03/03/2023 from 10:00 AM to 3:00 PM.
3. Date and time for submission of Tender form : 10/03/2023 from 10:00 AM to 12:00 Noon.
4. Date and time for opening of tender : 10/03/2023 from 1:30 PM
5. No tender shall be entertained after the expiry of the above schedule date and time.
6. Tender form/documents could be obtained from the office of the Senior Accounts Officer, S&YAD. The prescribed Non-transferable tender documents (excluding the tender form) can be obtained on production on requisite Bank Receipt o the State Bank of Sikkim towards the cost of tender documents (Non-refundable) under the Head "0202-03-800-01. Misc receipt" Cost of the tender form and submitted the same along with attested copies of the following documents:
   a. An application signed by the contractor for availing the Tender Documents.
   b. Validated/updated contractor Enlistment Certificate.

NOTE: It is necessary to produce original copies of the above documents certificates for verification at the time of issue of tender documents.

Sd/-
Superintending Engineer, S&YAD
Government of Sikkim

R.O. No.: 381/IPR/PUB/Classi/2223, DT.: 07.02.2023

वर्ष : 17 ❖ अंक : 184 ❖ पृष्ठ : 08 ❖ मूल्य : ₹ 3.00 ❖ आरएनआई सं. SIKHIN/2006/17890 ❖ www.anugamini.com

सिक्किम से प्रकाशित प्रथम हिन्दी दैनिक

अनुगामिनी

गंगटोक
गुरुवार, 09 फरवरी 2023

हम बिना शोर-शराबे के चुपचाप काम करने में विश्वास रखते हैं : सीएम गोले

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 08 फरवरी । सिक्किम के नेपाली समुदाय को संदर्भित कर अपने दिये गये बयान में त्वरित संशोधन कर मामले का समाधान करने हेतु राज्य मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) ने सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि सिक्किम का भारतीय न्यायपालिका पर अटूट विश्वास है और यहां के लोगों की भावनाओं को समझने और मामले को तुरंत हल करने के लिए वह न्यायालय के प्रति कृतज्ञ हैं।

अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर यह टिप्पणी करते हुए सीएम श्री तमांग ने यह भी स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय सिक्किम को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 371एफ को नहीं छूता है। उन्होंने इसे सिक्किम के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। इसके साथ ही इस मामले में सहयोग, समर्थन एवं एकजुटता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कानून मंत्री किरण रिजीजू के प्रति आभार भी व्यक्त किया है।

उन्होंने कहा कि हम अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आभारी हैं जिनके दूरदर्शी नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह जी ने हमारे साथ एकजुटता व्यक्त की और हमारा समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मुझे भारत के कानून मंत्री किरेन रिजिजू जी को सिक्किम के हर मुद्दे पर उनके द्वारा दिए गए समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहिए। उनकी आसान पहुंच, गर्मजोशी और प्रतिक्रिया हमेशा आश्वस्त करने वाली होती है।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री गोले ने वरिष्ठ अधिवक्ता और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन, सिक्किम के महाधिवक्ता डॉ श्रीमती डोमा छिरिंग भूटिया और राज्य के अन्य वकीलों को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सर्वोत्तम संभव तरीके से मामले को तैयार कर प्रस्तुत करने और बहस हेतु कड़ी मेहनत करने के लिए धन्यवाद दिया है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि हम बिना शोर-शराबे के चुपचाप काम करने में विश्वास रखते हैं और सिक्किम सरकार ने पहले दिन से ही इस मामले को पूरी गंभीरता के साथ उठाया है। एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हम कभी भी इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीतिक लाभ अर्जित करने की दौड़ में शामिल नहीं हुए। इसकी बजाय हमने केवल याचिका की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया।

मुख्यमंत्री गोले ने आगे कहा कि मैंने हमेशा परिणाम को लेकर धैर्य बनाए रखने की अपील की है। ऐसे में मैं प्रत्येक सिक्किमवासियों को यह विश्वास दिलाने के लिए धन्यवाद देता हूं कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहा हूं। राज्यवासियों का अपार समर्थन, प्यार, स्नेह और विश्वास ही मेरी ताकत है जो मुझे उनके लिए दिन-रात काम करने के लिए हमेशा प्रेरित करता है।

अदालत का निर्णय ऐतिहासिक : खालिंग

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 08 फरवरी । सुप्रीम कोर्ट ने गत 13 जनवरी को राज्य के नेपाली समुदाय को संदर्भित कर दिये गये अपने बयान पर राज्य और केंद्र सरकार द्वारा जारी पुनर्विचार याचिका पर आज सुनवाई करते हुए विवादित वाक्यांश को हटाने का फैसला किया है। इस पर सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने इसे ऐतिहासिक करार दिया है।

एसकेएम प्रवक्ता और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव जैकब खालिंग ने इस पर अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा है कि सिक्किम में नेपाली समुदाय से अवैध अप्रवास होने का कलंक हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्णय के बाद यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए खालिंग ने कहा कि अब सिक्किम के नागरिकों पर लगा कलंक पूरी तरह से मिट गया है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कानून मंत्री किरण रिजिजू और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने आगे कहा कि आज के फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सिक्किमियों को नुकसान नहीं होगा और उन्हें न्यायपालिका की सुरक्षा प्राप्त होगी।

वहीं 1994 में भी नेपाली समुदाय को बदनाम किए जाने की बात याद करते हुए खालिंग ने कहा कि पवन चामलिंग के नेतृत्व वाली एसडीएफ ने भले ही उस समय इसी मुद्दे पर सत्ता हासिल की थी, लेकिन उसने 25 साल तक इस मामले पर याचिका दर्ज नहीं की। लेकिन एसकेएम पार्टी के नेतृत्व वाली मौजूदा राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पहली सुनवाई के 28 दिन से भी कम समय में एक समीक्षा याचिका दर्ज करके इससे जुड़े कलंक को हटा दिया है। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से इस मुद्दे पर आवाज उठाने वाले सिक्किम के सभी लोगों के साथ-साथ दार्जिलिंग, कालिम्पोंग समेत पूरे देश के नेपालियों का आभार व्यक्त किया।

इसके साथ ही खालिंग ने मौजूदा मुद्दे को राजनीतिक नहीं, बल्कि सिक्किम का मुद्दा बताया और खेद व्यक्त करते हुए कहा कि कुछ

तत्वों ने इसका भी राजनीतिकरण किया और मुख्यमंत्री पीएस गोले का पुतला भी जला दिया। लेकिन जनता को उनके असली चेहरे का एहसास हुआ और उनलोगों ने इसके लिए राज्यव्यापी बंद को पूरी तरह से विफल कर दिया है।

जेएसी के बंद को मिला भरपूर समर्थन, दुकान-बाजार रहे बंद

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 08 फरवरी । राज्य के ओल्ड सेटलर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले में सिक्किम के नेपाली समुदाय को 'अप्रवासी' बताने और 'सिक्किमीज' शब्द को हटाने के खिलाफ राज्य में ज्वाइंट एक्शन कमेटी (जेएसी) की ओर से आज 12 घंटे बंद का आयोजन किया गया। बंद का पूरे सिक्किम पर व्यापक प्रभाव पड़ा।

जेएसी की ओर से बुलाए गए बंद को सत्ताधारी एसकेम और विपक्षी एसडीएफ के साथ ही अन्य राजनीतिक दलों का भी समर्थन प्राप्त था।

जेएसी ने शांतिपूर्ण बंद को लागू करने के लिए धरना देने के लिए राज्य भर में सदस्यों की प्रतिनियुक्ति की थी। बंद के दौरान न तो नारेबाजी हुई और न ही कोई रैली निकाली गई।

प्रदेश भाजपा ने किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 08 फरवरी । भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 13 जनवरी को राज्य के ओल्ड सेटलर्स की याचिका पर निर्णय में विवादित वाक्य को हटा दिया है। अदालत के इस फैसले का प्रदेश भाजपा ने स्वागत किया है।

प्रदेश भाजपा प्रवक्ता डा राजू गिरी ने यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि इस मामले में सिक्किम के लोगों की भावनाओं की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर गृह मंत्री अमित शाह के गंभीर हस्तक्षेप के बाद आज देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सिक्किम के नेपाली लोगों पर लगाए गए विदेशी टैग को हटा दिया है।

प्रदेश भाजपा ने इस ऐतिहासिक क्षण पर सिक्किम के पूरे लोगों को बधाई दी है और प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और कानून मंत्री के प्रति अपनी कृतज्ञता और धन्यवाद व्यक्त किया है।

भाजपा ने कहा कि 13 जनवरी, 2023 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर पिछले कुछ हफ्तों से सिक्किम में तीखा विरोध और लोकप्रिय आंदोलन चल रहा था। 5 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष एवं अपर बर्तुक विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री डीआर थापा के नेतृत्व में भाजपा विधायक दल के नेता श्री एनके सुब्बा, वरिष्ठ विधायक डीटी लेप्चा, संयुक्त कार्यवाही समिति और सिक्किम नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के साथ महत्वपूर्ण बैठक की थी। गृह मंत्रालय ने इस मुद्दे पर गंभीरता से हस्तक्षेप किया और पुनर्विचार याचिका दायर की थी।

इस ऐतिहासिक जीत पर सिक्किम के सभी लोगों को बधाई देते हुए, भारतीय जनता पार्टी पूरे सिक्किम के लोगों को आश्वस्त करना चाहती है कि सिक्किम के अस्तित्व को नुकसान पहुंचाने की साजिश होने पर सिक्किम और सिक्किम के लोगों के अस्तित्व की रक्षा के लिए वे एक दीवार के रूप में खड़े होंगे।

अप्रवासी विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने फैसले से विवादित वाक्य को हटाया

कहा- संशोधित याचिका संज्ञान में नहीं लाने के कारण हुई त्रुटी

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 08 फरवरी । सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में उन टिप्पणियों को हटा दिया, जिसमें सिक्किमी-नेपाली व्यक्तियों को 'विदेशी मूल के लोग' के रूप में वर्णित किया गया था। एसोसिएशन ऑफ ओल्ड सेटलर्स ऑफ सिक्किम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में दिए गए फैसले में की गई टिप्पणी के खिलाफ सिक्किम में विरोध तेज हो गए थे। फैसले में सिक्किमी-नेपाली समुदाय ने कड़ी आपत्ति जताई थी।

मामले में यूनियन ऑफ इंडिया, सिक्किम राज्य और तीसरे पक्ष ने संशोधनों की मांग करते हुए आवेदन दायर किए थे। यह फैसला जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने सुनाया था। विवादास्पद हिस्सा जस्टिस नागरत्ना द्वारा लिखे गए फैसले में था, जो इस प्रकार था, 'इसलिए, सिक्किम के मूल निवासियों, अर्थात् भूटिया-लेप्चा और सिक्किम में बसे विदेशी मूल के व्यक्तियों के बीच कोई अंतर नहीं किया गया था, जैसे कि नेपाली या भारतीय मूल के व्यक्ति जो पीढ़ियों पहले सिक्किम में बस गए थे'।

पीठ शुरू में, 'नेपालियों की तरह सिक्किम में बसे विदेशी मूल के व्यक्तियों' के हिस्से को हटाने पर सहमत हुई। हालांकि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अनुरोध किया कि पूरे वाक्य को हटा दिया जाए। पीठ तब 'भूटिया लेप्चा और नेपाली की तरह सिक्किम में बसे विदेशी मूल के व्यक्तियों' के हिस्से को हटाने पर सहमत हुई। आज अर्जियों पर सुनवाई करते हुए बेंच ने कहा कि रिट याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में कुछ संशोधन किए थे, जिन्हें कोर्ट के संज्ञान में नहीं लाया गया।

अदालत ने कहा कि यह नोट किया गया है कि उक्त रिट याचिका में दायर एक आवेदन के अनुसार एक संशोधित रिट याचिका दायर की गई थी... दुर्भाग्य से रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने इस अदालत के ध्यान में पर्याप्त संशोधनों को नहीं लाया। अदालत के नोटिस के लिए यह लाना उनका कर्तव्य था। अब एमए को सुधार की मांग करते हुए दायर किया गया है जैसे कि अदालत की ओर से त्रुटि हुई है... हालांकि, संबंधित पक्षों के सीनियर काउंसल को सुनने के बाद, हमें लगता है कि कुछ शब्दों को सही करना उचित है, जिन्हें मेरे फैसले में अनुच्छेद 10ए और 68.8 में इस्तेमाल किया गया।

इस मामले में दिए गए निर्णय में कहा गया है कि 26.04.1975 को सिक्किम के भारत में विलय से पहले सिक्किम में स्थायी रूप से बसने वाले पुराने भारतीय निवासियों को आयकर अधिनियम की धारा 10 (26एएए) में 'सिक्किमीज' की परिभाषा से बाहर करना असंवैधानिक था। यह टिप्पणी, जो सिक्किम के इतिहास का वर्णन करते समय की गई थी और फैसले में अंतिम तर्क पर कोई असर नहीं पड़ा। इन शब्दों के कारण सिक्किम में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया गया था।

सॉलिसिटर जनरल ने स्पष्टीकरण देने के लिए एक और अनुरोध किया कि निर्णय ने अनुच्छेद 371 एफ के पहलू को नहीं छुआ है। हालांकि, पीठ ने कहा कि स्पष्टीकरण अनावश्यक है क्योंकि अनुच्छेद 371 एफ मामले का विषय नहीं था।

अदालत के इस निर्णय के सामनेत आते ही सिक्किम में वृहत स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे।

कोर्ट की टिप्पणी से आहत नेपाली समुदाय के लोगों ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से शांति सद्भाव कायम करने की अपील की थी। उन्होंने इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का आश्वासन दिया था। आज सरकार की ओर से एसजी तुषार मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सिक्किम का नेपाली समुदाय काफी आहत है। इस कारण वह विरोध प्रदर्शन कर रहा है। सिक्किम के नेपाली समुदाय को भारत सरकार विदेशी नहीं मानती है। इसको लेकर नेपाली समुदाय काफी आक्रोशित भी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस टिप्पणी को वापस लेने के फैसले के बाद नेपाली समुदाय में एक खुशी की झलक दिखी है।

कोर्ट ने इस टिप्पणी को वापस लेने का फैसला तो किया है साथ ही कहा है कि इस केस से जुड़े वकीलों को नेपाली समुदाय के आहत लोगों से माफी मांगनी चाहिए। किसी के भी दिल को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने पहले यह कोर्ट के नोटिस में नहीं लाया गया था। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में खामियों के चलते संशोधित याचिका दायर की लेकिन यह बात कोर्ट के ध्यान में नहीं लाई गई थी।

शोषण का खेल

हाल में कुछ महिला खिलाड़ियों या प्रशिक्षकों की ओर से यौन शोषण की शिकायतों से उठा मसला अभी किसी हल तक नहीं पहुंचा है कि अब दिल्ली में एक कबड्डी खिलाड़ी ने अपने प्रशिक्षक पर बलात्कार और भयादोहन का आरोप लगाया है।

पुलिस के पास दर्ज मामले के मुताबिक एक महिला खिलाड़ी का कहना है कि उसका प्रशिक्षक न सिर्फ सात साल से बलात्कार कर रहा है, बल्कि उसने धमकी देकर उससे काफी धन भी ऐंठ लिए। गौरतलब है कि पीड़ित महिला एशियाई खेलों में देश के लिए रजत पदक जीतने वाली कबड्डी टीम की खिलाड़ी रही है।

आम आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्ति की महिलाओं के खिलाफ हरकतें छिपी नहीं हैं, लेकिन खेलों की दुनिया में इस तरह की घटनाएं ज्यादा शर्मनाक हैं। सवाल है कि प्रशिक्षक जैसी महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी को ताक पर रख कर कोई व्यक्ति महिलाओं के खिलाफ अपराधियों जैसी हरकतें कैसे करने लगता है!

महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण की घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं। कई बार हालात की जटिलता की वजह से कुछ महिलाएं अपने शोषण के खिलाफ बोल भी नहीं पातीं। यह कोई छिपी बात नहीं है कि महिलाओं का घर की दहलीज से बाहर निकल कर पढ़ना-लिखना और उससे आगे खेलों की दुनिया में अपनी जगह बनाना आज भी किस तरह की चुनौतियों से घिरा हुआ है।

होना यह चाहिए था कि अगर कोई लड़की किसी खेल में अपनी काबिलियत साबित करना चाहती है तो उसका हौसला बढ़ा कर न सिर्फ बेहतरीन प्रशिक्षकों के जरिए उसकी प्रतिभा को निखारा जाए, बल्कि देश और समाज के हक में भी उसे एक उदाहरण बनाया जाए। लेकिन अफसोसनाक यह है कि एक पारंपरिक ढांचे के समाज में तमाम अड़चनों से निकल कर किसी खेल में अपने और देश के लिए कुछ करने का सपना पालने वाली लड़की का अपराधी कई बार उसका प्रशिक्षक ही निकल जाता है। जिसके भरोसे कोई लड़की किसी खेल में देश को एक नई ऊंचाई देना चाहती है, वही प्रशिक्षक उसके व्यक्तित्व और सपने को छिन्न-भिन्न कर डालता है।

सही है कि खेलों की दुनिया में सभी लोग ऐसी आपराधिक मानसिकता वाले नहीं होते। ऐसे प्रशिक्षकों की लंबी सूची है, जिनके निर्देशन और सहयोग के बूते बहुत सारी महिला खिलाड़ियों ने दुनिया भर में अपनी काबिलियत साबित की है। मगर इसी बीच कुछ प्रशिक्षकों की आपराधिक हरकतों की वजह से किसी महिला खिलाड़ी के टूट जाने की खबरें भी आती हैं। हाल ही में कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण के आरोपों के अलावा हरियाणा में खुद खेलमंत्री के एक महिला प्रशिक्षक से अवांछित बर्ताव की जैसी खबरें आईं, वे बताती हैं कि खेलों के शासकीय तंत्र में व्यापक सुधार की जरूरत है।

खासकर अगर कोई व्यक्ति महिला खिलाड़ियों के प्रशिक्षण जैसे जिम्मेदारी से भरे काम में लगाया जाता है तो क्षमताओं के साथ-साथ उसकी मानसिकता, प्रवृत्ति और कुंठाओं आदि की जांच-परख भी होनी चाहिए। महिला खिलाड़ियों के किसी भी तरह के शोषण की आशंका तक की स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वरना बहुस्तरीय बाधाओं को पार कर किसी खेल के मैदान में आईं और इसमें ऊंची उड़ान का सपना देखने वाली लड़कियों का रास्ता मुश्किल बना रहेगा।

स्वास्थ्य ढांचे के लिए गंभीर चुनौती

योगेश कुमार गोयल

हालांकि महामारी विज्ञान के अध्ययनों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि कैंसर के 70-90 फीसद मामले पर्यावरण से जुड़े हैं, जिनमें कैंसर का कारण बनने वाले पर्यावरणीय जोखिमों में जीवनशैली सबसे महत्त्वपूर्ण कारक है, जिसमें सुधार करके कैंसर की सुनामी को रोका जा सकता है।

दुनिया भर में कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ग्लोबल कैंसर आब्जर्वेटरी (ग्लोबोकान) के मुताबिक जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के चलते विश्वभर में 2040 तक कैंसर के मामले प्रतिवर्ष 2.84 करोड़ तक पहुंच सकते हैं, जो 2020 के मुकाबले सैंतालीस फीसद ज्यादा होंगे। 2020 में दुनिया भर में कैंसर के करीब 1.93 करोड़ नए मामले आए थे और लगभग एक करोड़ लोगों की इससे मौत हुई थी। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के अनुसार कैंसर मरीजों की संख्या वैश्वीकरण और बढ़ती अर्थव्यवस्था से जुड़े जोखिमों के चलते बढ़ सकती है।

भारत में कैंसर के बढ़ते मामले देश के स्वास्थ्य ढांचे के लिए गंभीर चुनौती बन रहे हैं। वर्ल्ड कैंसर रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2018 में कैंसर के करीब 11.6 लाख मामले आए थे, जिनमें से 7,84,800 लोगों की मौत हो गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन और उसके साथ कार्य करने वाली संस्था इंटरनेशनल एजेंसी फार रिसर्च आन कैंसर भी भारत को लेकर कुछ चिंताजनक रिपोर्टें जारी कर चुकी है, जिनमें कहा गया है कि प्रत्येक दस भारतीय में से एक को कैंसर होने और प्रत्येक पंद्रह में से एक व्यक्ति की कैंसर से मौत होने की आशंका है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) के अनुसार दुनिया के बीस फीसद कैंसर मरीज भारत में हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) की ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में आगामी पांच वर्षों में कैंसर के मामले बारह फीसद तक बढ़ जाएंगे और 2025 तक कैंसर मरीजों की संख्या 15.69 लाख के पार हो जाएगी। पुरुषों में फेफड़ों, मुंह, पेट और श्वासनली में कैंसर सबसे आम है, जबकि महिलाओं में स्तन कैंसर के मामले तेजी से बढ़े हैं।

अमेरिका के जाने-माने कैंसर विशेषज्ञ डा जेम अब्राहम ने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में भारत को कैंसर जैसी लंबे समय तक परेशान करने वाली बीमारियों की सुनामी का सामना करना पड़ सकता है। उनके मुताबिक वैश्वीकरण, बढ़ती अर्थव्यवस्था, बढ़ती आबादी और बदलती जीवनशैली के कारण भारत में कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों के मामले बहुत तेजी से बढ़ेंगे।

हालांकि उनका कहना है कि कैंसर की रोकथाम और उपचार के लिए टीके, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा डिजिटल तकनीक का विस्तार, लिक्विड बायोप्सी से निदान, जीनोमिक प्रोफाइलिंग, जीन संपादन प्रौद्योगिकियों का विकास और अगली पीढ़ी के इम्युनोथैरेपी तथा सीएआरटी सेल थेरेपी का इस्तेमाल कैंसर के उपचार को नया रूप देंगे और डिजिटल तकनीक, सूचना प्रौद्योगिकी तथा टेली-हेल्थ से मरीजों और विशेषज्ञों के बीच की खाई कम होगी। पिछले कुछ वर्षों में कैंसर पर विभिन्न टीके तैयार किए गए हैं, फिलहाल इन पर परीक्षण हो रहे हैं, जिनके पहले चरण में सफलता मिली है।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री ने जुलाई 2022 में संसद में एक सवाल के जवाब में बताया था कि देश में 2018 में कैंसर मरीजों की संख्या 13,25,232 थी, जो 2019 में बढ़ कर 13,58,415 और 2020 में 13,92,179 तक पहुंच गई। 2018-2020 में दो वर्षों में कैंसर के मामलों में पांच फीसद यानी करीब 67 हजार की वृद्धि हुई। भारत में कैंसर के बढ़ते मामलों को लेकर दिसंबर 2022 में राज्यसभा में आधिकारिक आंकड़ों के हवाले से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया था कि देश में पिछले दो वर्षों के भीतर कैंसर से मौत के मामले बढ़े हैं। इससे अनुमानित मृत्यु दर 2020 में 7,70,230 थी, जो 2021 में बढ़ कर 7,89,202 और 2022 में 8,08,558 हो गई।

देश में कैंसर के मामलों में चालीस फीसद से ज्यादा मरीज फेफड़े, स्तन, अन्नप्रणाली यानी ईसोफेगस, मुंह, पेट, यकृत यानी लीवर और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से पीड़ित हैं, जिनमें फेफड़ों के कैंसर से 10.6 फीसद, स्तन कैंसर से 10.5, अन्नप्रणाली कैंसर से 5.8, मुंह के कैंसर से 5.7, पेट के कैंसर से 5.2, लीवर कैंसर से 4.6 और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से 4.3 फीसद लोग पीड़ित हैं। आइसीएमआर के मुताबिक कैंसर के मामले महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज्यादा देखे जा रहे हैं।

2021 में उत्तर भारत में प्रति एक लाख व्यक्ति पर 2408 और पूर्वोत्तर में प्रति एक लाख व्यक्ति पर 2177 कैंसर रोगियों के मामले सामने आए। मुंह, फेफड़े, पेट, कोलोरेक्टल, ग्रसनी, ग्रासनली आदि के कैंसर के अलावा अन्य कैंसर की दर भी भारतीय पुरुषों में प्रति एक लाख पर पांच या उससे ज्यादा मरीजों की है। महिलाओं में स्तन, गर्भाशय ग्रीवा तथा कोलोरेक्टल कैंसर के सर्वाधिक मामले सामने आते हैं और इनके अलावा अन्य प्रकार के कैंसर के मामले महिलाओं में प्रति एक लाख पर पांच से कम दर्ज किए गए हैं।

आइसीएमआर तथा नेशनल सेंटर फार डिजीज इन्फारमेटिक्स एंड रिसर्च (एनसीडीआईआर) द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक 7.6 लाख पुरुषों और 8.1 लाख महिलाओं को कैंसर हो सकता है। भारत में कैंसर के कुल मामलों का करीब 27 फीसद तंबाकू जनित होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा स्तन कैंसर के 2.4 लाख मामले सामने आने का अनुमान है, जबकि फेफड़ों के कैंसर के 1.1 लाख तथा मुंह के कैंसर के 90 हजार मामले सामने आ सकते हैं।

रिपोर्ट में 2020 में कैंसर के कुल मामलों में 27.1 फीसद (3.71 लाख) मामले तंबाकू से संबंधित कैंसर के, 14 फीसद (2 लाख) महिलाओं में सर्वाधिक होने वाले स्तन कैंसर के, 5.4 फीसद (75 हजार) मामले सर्विक्स कैंसर के और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट कैंसर (भोजन नली का कैंसर) के करीब 19.7 फीसद (2.7 लाख) मामले होने का अनुमान था। भोजन नली का कैंसर आगामी वर्षों में दूसरी तरह के कैंसर के मुकाबले ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में लेगा।

देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कैंसर के मामले सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। उनमें तंबाकू से जुड़े कैंसर के मामले सर्वाधिक हैं और ये पुरुषों में ज्यादा हैं। भारत में कैंसर के सर्वाधिक मामले मिजोरम की राजधानी आइजल में सामने आए हैं, जहां पुरुषों की प्रति एक लाख आबादी पर 269.4 कैंसर मरीज हैं। वहीं महिलाओं में अरुणाचल प्रदेश के पपुम्परे जिले में प्रति लाख आबादी पर 219.8 मामले हैं। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार पुरुषों में होने वाले कैंसर के पचास फीसद मामले तंबाकू के कारण होते हैं, जबकि बीस से तीस फीसद मामले खानपान, प्रजनन और यौन व्यवहार आदि से जुड़े हैं।

हालांकि महामारी विज्ञान के अध्ययनों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि कैंसर के 70-90 फीसद मामले पर्यावरण से जुड़े हैं, जिनमें कैंसर का कारण बनने वाले पर्यावरणीय जोखिमों में जीवनशैली सबसे महत्त्वपूर्ण कारक है, जिसमें सुधार करके कैंसर की सुनामी को रोका जा सकता है। जीवनशैली में आए बड़े बदलावों के कारण भी कैंसर के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है।

दरअसल, आज के आधुनिक युग में लोग न केवल तेजी से शहरों की ओर रुख कर रहे हैं, बल्कि पुरानी पीढ़ियों की तुलना में उनके आहार और रहन-सहन में बड़ा बदलाव आ रहा है। जीवनशैली में आ रहे ऐसे बदलावों का असर शरीर पर धीरे-धीरे दिखता है और परिणाम कई बार कैंसर जैसी बीमारी के रूप में सामने आता है।

आज देश में कैंसर के बढ़ते मामलों के लिए गतिहीन जीवनशैली, जंक फूड, शराब तथा तंबाकू का सेवन और खराब वायु गुणवत्ता आदि कई कारण जिम्मेदार हैं, जो शरीर की कोशिकाओं की संरचना में बदलाव का कारण बनते हैं। बहरहाल, देश में कैंसर मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर कैंसर विशेषज्ञों और चिकित्सकों का साफतौर पर यही कहना है कि अगर लोगों की आदतों और जीवनशैली में अपेक्षित बदलाव नहीं आया, तो आने वाले वर्षों में स्थितियां और बिगड़ेंगी।

जाति-धर्म में न उलझे देश

डॉ. सी.पी. राय

जहां दुनिया और मानवता के सामने फिलवक्त बड़ी चुनौतिया हैं।

दुनिया के सारे देश भविष्य की चुनौतियों का आकलन करने में तथा उससे निपटने में अपनी संपूर्ण मेधा को झोंके हुए है; वहीं भारत में काफी संख्या में राजनीतिक नेतृत्व आज भी जाति और धर्म के विमर्श को ही मुख्य विमर्श बनाने में अपनी पूरी ऊर्जा खपाए हुए है।

नब्बे के दशक से भारत ने धर्म के नाम पर काफी बदनामी और तबाही झेली है और जाति के नाम पर भी उलझन में रहा है। इस वक्त कोविड महामारी के बाद की दुनिया बेरोजगारी, तरह-तरह की बीमारी, मंदी इत्यादि से जूझ रही है, साथ ही आने वाली चुनौतियों को लेकर बेचैन है। इसके अलावा पर्यावरण, ग्रीन गैसों के आतंक, प्रदूषण तथा गैस उत्सर्जन के कारण तरह-तरह के होते बदलाव को लेकर भी चिंतित है। जहां गर्मी पड़ती थी वहां ठंड रफ्तार पकड़ रही है तथा यूरोपीय देशों में 45-46 के बढ़ते तापमान ने लोगों को परेशान कर रखा है। जल संकट आने वाले समय की बड़ी चुनौती बनता दिख रहा है तो भारत में राजनैतिक नेतृत्व मानो सभी तथ्यों से बेखबर कभी हिंदू बनाम मुसलमान तो कभी मंदिर-मस्जिद में उलझा हुआ दिखता है; कभी रामचरितमानस तो कभी हरिजन या एससी-एसटी बनाम शूद्र में तो कभी पिछड़ों की पहचान में और देश को सैकड़ों साल पहले की बहस में घसीट कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ले रहा है। इसे वैचारिक दिवालियापन ही कहा जाएगा।

भारत इस वक्त 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी का शिकार है। पहले नोटबंदी और फिर कोविड महामारी ने अर्थव्यवस्था को बड़ा धक्का पहुंचाया है। बहुत बड़ी तादाद में नौकरियां चली गई तो न जाने कितने कारोबार बंद हो गए। कोविड के कारण अकारण लोगों की मौतें हों या अर्थव्यवस्था के प्रभाव से आत्महत्याएं; इनके आंकड़े डराते हैं। सरकारी भर्ती या तो रु की हुई है या फिर पद घट रहे हैं या निजीकरण की रफ्तार का प्रभाव है कि रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं। ऐसे में लड़ाई और विमर्श तो इस बात पर होनी चाहिए कि रोजगार के अवसर कैसे बढ़े या विकेंद्रित कारोबार कैसे बढ़े, स्वरोजगार के अवसर कैसे बढ़े?

ऐसी परिस्थिति में जब पूंजी का केंद्रीकरण ही बढ़ रहा हो, अंधाधुंध शहरीकरण के कारण कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही हो, गांवों की अव्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं के अभाव में शहरों की तरफ पलायन बढ़ रहा है तो बढ़ती आबादी में परिवारों में बंटवारा होने के करण खेत के छोटे-छोटे टुकड़े होते जा रहे हों, जो किसी भी दृष्टि से लाभदायक नहीं है और परिवार का बोझ उठाने में भी असमर्थ साबित हो रहे हैं। चिकित्सा और शिक्षा महंगी होती जा रही है। देश में आर्थिक विषमता सिर्फ बढ़ ही नहीं रही है बल्कि सुरसा की तरह बढ़ती जा रही है। सौ घरानों के पास देश की 90 फीसद से ज्यादा संपदा हो गई है। पड़ोसी देशों की चुनौतियां भी मुंह बाये खड़ी है। ऐसे में जिन मुद्दों का इंसानों की बेहतरी से कोई संबंध नहीं है और कम-से-कम 90 फीसद से ज्यादा लोगों का तो कोई संबंध नहीं है; उन मुद्दों से देश को भटकाना क्या देश और समाज के साथ गद्दारी नहीं है।

सबसे बड़ा सवाल तो यही पूछा जाना चाहिए कि कोरोना के वक्त धर्म और धार्मिक संगठनों ने आमजन की कितनी मदद की या जातीय संगठन तथा कथित ठेकेदारों ने लाचार लोगों को कितनी मदद की? इसी परिप्रेक्ष्य में एक सवाल पूछ लिया जाए कि इन वर्षों में धर्म का इस्तेमाल सिर्फ राजनीति और वोट के अलावा और किस रूप में हुआ है? क्या इसके ठेकेदार इस बात का दावा करते हुए आंकड़े दे सकते हैं कि इन विवादों के छिड़ने के बाद से आबादी में कितनों में राम, लक्ष्मण, भरत के गुणों का विकास हुआ या कितनों ने सचमुच में राम जैसी मर्यादा, लक्ष्मण का समर्पण, भरत का आदर्श अपनाया है? असल में तो यही प्रतीत होता है कि रावण और कैकेयी जैसों की संख्या ही बढ़ रही है?

कितनों ने कृष्ण से या महाभारत से शिक्षा ली है? क्या यह आश्चर्यजनक तथ्य नहीं है कि जितनी चर्चा धर्म की बढ़ी और धर्मस्थल कदम-कदम पर बने उतना ही धर्म और ईश्वर का डर खत्म हो गया। तभी तो चारों तरफ पाप बढ़ा हुआ है और धर्म के ठेकेदारों ने साभी पापियों के लिए पाप करने के बाद उसे धोने के रास्ते भी निकाल लिये हैं। क्या यह सच नहीं है कि सीता के वनगमन का दृश्य देखकर आंसू बहाने वाले लोग फिल्म या धारावाहिक खत्म होते ही बीबी को पीटने लगते हैं, भारत मिलाप के दृश्य पर सुबकने वाले अपने ही भाई से मुकदमा लड़ रहे होते हैं या उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे होते हैं, द्रौपदी के चीरहरण पर दुखी होने वाले अपने बहुत करीबी से या आसपास चीरहरण से भी ज्यादा घृणित काम कर बैठते हैं। रोज इन समाचारों से अखबार रंगे रहते हैं।

सवाल है कि फिर सभी धार्मिक पुस्तकों और प्रतीकों ने अपने मानने वालों पर क्या प्रभाव डाला है? अगर कुछ नहीं तो उनका उपयोग क्या है? यही सवाल जातियों के ठेकेदारों से भी है कि क्यों नहीं कोई दूसरा महत्मा फुले या बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर पैदा हो पाए आजतक? और कैसे जातियों के उत्थान के नाम पर सत्ता पाए लोग अरबपति-खरबपति बन गए। ऊंच बनाम नीच की लड़ाई लड़ते-लड़ते लोग खुद ऊंचे बन जाते हैं। भारत का नौजवान क्या पिछली शताब्दी में ही अटका है या इस प्रतिस्पर्धी युग में उसका मुकाबला करने और उस चुनौती को स्वीकार कर आगे बढ़ने की मानसिकता बना चुका है जिसके परिणामस्वरूप वह जाति और धर्म से उठकर देश और दुनिया में नौकरी हो या व्यापार या अनुसंधान सभी में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सके।

किसी भी देश और समाज के नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने यहां धार्मिक और सामाजिक कटुता दूर करे, अंधविश्वास खत्म करे और इतिहास की कटुता से अपने समाज और देश को दूर करने का जरिया बने। नई पीढ़ी को नया प्रगतिशील समाज और देश बनाने को प्रेरित करे न कि पुरानी कटुता अगली पीढ़ी को सौंपे। फिर भी जो लोग ऐसा करते हैं वो वैसे लोग हैं जिनके पास देश, समाज और मानवता के लिए कोई सार्थक सपने नहीं है, सिद्धांत नहीं है, जबकि आम भारतीय तो अपने दैनंदिनी संघर्ष से जूझ कर हल ढूंढ रहा है। इसे जाति और धर्म में उलझा कर अज्ञानी नेतृत्व मुद्दों से मुंह छुपाना चाहता है। देश और समाज को इन लोगों को आईना दिखाना ही होगा तभी ऐसे लोगों से मुक्ति मिलेगी।

सवालों के घेरे में सिस्टम

संदीप भूषण

नब्बे के दशक में सुपर स्टार बेन जॉनसन का जलवा हुआ करता था। सियोल ओलंपिक में 100 मीटर दौड़ 9.79 सेकेंड में पूरी कर उन्होंने सबको चौंका दिया था।

हालांकि, उनके साथी धावक कार्ल लुईस को उनके इस प्रदर्शन पर शक था। उन्होंने तब सार्वजनिक तौर पर कहा भी था कि जॉनसन की इस तेजी में कुछ गड़बड़ी है। बाद में खेलों के महाकुंभ में डोपिंग का बम फूटा और लुईस की आशंका सच साबित हुई। जॉनसन के नमूने पॉजिटिव पाए गए और उनसे पदक छीन लिया गया। इस घटना ने अंतरराष्ट्रीय जगत को सकते में ला दिया। खेलों में नशीले पदार्थ का सेवन रोकने की जिम्मेदारी उठाने वाली विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने सख्ती बरतनी शुरू की। बावजूद इसके अब तक रूस और अमेरिका सहित कई देश के खिलाड़ियों को डोपिंग का दोषी पाया जा चुका है।

भारत भी इस कलंक से अछूता नहीं है। 1968 में दिल्ली में आयोजित मैक्सिको ओलंपिक ट्रायल के दौरान कृपाल सिंह से लेकर पहलवान नरसिंह तक इसके जाल में फंस चुके हैं। ताजा मामला जिमनास्ट दीपा कर्माकर का है। अरबों रु पये खर्च करने के बाद भी खिलाड़ियों का डोपिंग में फंसना हमारे समूचे खेल सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। साथ ही खेल में महाशक्ति बनने के हमारे सपने में भी बाधा बन रहा है।

दरअसल, प्रतियोगिता से इतर लिये गए दीपा के नमूने पॉजिटिव पाए गए हैं। रियो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन से चौथे स्थान पर रही दीपा पर 21 महीने का प्रतिबंध लगा। उन्होंने सजा स्वीकार कर ली, लेकिन कहा कि उन्होंने अनजाने में इसका सेवन किया था। गौरतलब है कि भारतीय खेल जगत में अब तक जितने भी खिलाड़ी डोपिंग में फंसे हैं, उनमें से ज्यादातर ने स्वीकार किया कि कम जानकारी या अनजाने में ही उन्होंने प्रतिबंधित दवाओं का सेवन किया।

सवाल उठता है कि आखिर महासंघ, कोच, डॉक्टर और डाइटिशियन खिलाड़ियों को डोपिंग संबंधी जानकारी मुहैया कराने में असफल क्यों हो रहे हैं? कब तक खिलाड़ियों की मेहनत पर अनजाने में की गई एक छोटी सी गलती भारी पड़ती रहेगी? अगर खिलाड़ी दोषी है तो उसके कोच और डाइटिशियन को भी इसका दोषी क्यों नहीं माना जाना चाहिए? विशेषज्ञों की मानें तो डोपिंग में किसी खिलाड़ी के फंसने के मुख्य कारण महासंघ, कोच और डाइटिशियन की लापरवाही के साथ खिलाड़ियों में जागरूकता की कमी है। यह तथ्य महत्त्वपूर्ण है कि भारतीय एथलेटिक्स में ज्यादातर खिलाड़ी ग्रामीण पृष्ठभूमि के आते हैं। जाहिर है कि खेल को डोपिंग मुक्त बनाने के लिए केंद्र के साथ राज्य सरकारों को भी मिलकर काम करने की जरूरत है।

हरियाणा, पंजाब, ओडिशा और झारखंड जैसे राज्य इसमें अग्रणी की भूमिका निभा सकते हैं, जहां से सबसे ज्यादा एथलीट आते हैं। निस्संदेह इन सबके साथ राज्यों को खेल ढांचा मजबूत करने के साथ डोपिंग के मुद्दे पर भी जागरूकता अभियान भी चलाना होगा। यह पहल कई जगह शुरू भी हुई है। आगे इसको और संगठित और प्रभावी तरीके से चलाने की जरूरत है। गौरतलब है कि अब तक की स्थिति में भारतीय खेल को खासा नुकसान उठाना पड़ा है कि शुरुआती दौर में खिलाड़ियों को अपने निजी कोच से उन्हें सिर्फ खेल निखारने की ही जानकारी मिल पाती है। उन्हें नहीं पता होता कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की प्रतिबंधित लिस्ट में किन-किन दवाइयों को शामिल किया गया है। भारत में तो कई मामले ऐसे भी आए जब जूनियार और सीनियर खिलाड़ी खांसी या मामूली बुखार में दवा का सेवन करते हैं और उनके नमूने डोपिंग में पॉजिटिव पाए जाते हैं।

दूसरी तरफ, जिस महासंघ या कोच पर खिलाड़ियों को जागरूक करने की जिम्मेदारी होती है, वे इससे पल्ला झाड़ लेते हैं। बीते कुछ दिनों में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ-साथ जूनियर खिलाड़ियों में भी डोपिंग के मामले देखे जा रहे हैं। इस मामले में आए कई विश्लेषण रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इसके पीछे खिलाड़ियों पर बेहतर प्रदर्शन का दबाव है। खिलाड़ियों को पता होता है कि चाहे सरकारी नौकरी हो, सर्वश्रेष्ठ स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश पाना हो या विज्ञापन व अन्य आर्थिक लाभ के लिए अलग-अलग लीग और कंपनियों से अनुबंध पाने की, एक बेहतर प्रदर्शन उनकी सफलता का मार्ग सुनिश्चित करेगा। बेहतर प्रदर्शन के लिए माता-पिता, शिक्षकों, प्रशिक्षकों और साथी प्रतिस्पर्धियों का दबाव होता है।

भारत सरकार खेल बजट को हर साल बढ़ा रही है। खिलाड़ियों को देश में विदेशी कोच मुहैया कराना हो या विदेश कोचिंग के लिए भेजना, उन्हें हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। हालांकि, आज भी डोपिंग रोधी नियमों को लेकर जागरूता फैलाने के मामले में सीनियर और जूनियर एथलीटों के बीच अंतर नजर आता है। साथ ही जूनियर स्तर के खिलाड़ियों के बीच नमूनों की जांच की संख्या भी बेहद कम है। इसका बड़ा कारण डोपिंग टेस्ट पर आने वाला खर्च है। महासंघ और नाडा उन खिलाड़ियों के नमूने लेने से बचती है, जो तुरंत किसी प्रतियोगिता में नहीं भाग ले रहे हैं। इसका भी खिलाड़ियों पर असर पड़ता है।

बहरहाल, भारतीय खेल प्रधिकरण का दावा है कि वह एक ऐसा ऐप विकसित कर रहा है, जिससे कोई भी खिलाड़ी आसानी से प्रतिबंधित दवाओं की जानकारी ले सकेगा।

ये है दुनिया का सबसे डरावना और वीरान आइलैंड, कभी इस बीमारी से पीड़ितों को बिना इलाज के रखा जाता था यहां

कोढ़ रोग को हमारे समाज में हमेशा से ही हीन भावना से देखा जाता है। इस बीमारी को भगवान का शाप या दंड माना जाता रहा है। समाज में लोग कोल्ड रोगियों से हमेशा दूरी बना कर रहे हैं। सदियों से इस बीमारी से पीड़ित लोगों को समाज से अलग रखा गया है। भारत ही नहीं दुनिया के विदेशों में कुष्ठ रोगियों के लिए कई आश्रम चलते हैं। लेकिन यूरोप के ग्रीस और यूनान जैसे देशों ने अपने यहां के कुष्ठ रोगियों को आम लोगों से दूर रखने के लिए एक आईलैंड ही अलग कर दिया था।

इस आइलैंड का नाम स्पिनालॉन्गा आइलैंड है। ये यूनान के सबसे बड़े क्रीट द्वीप के पास स्थित है। ये भूमध्य सागर में मिराबेलो की खाड़ी के मुहाने पर मौजूद है। लेकिन आज इस आईलैंड पर कोई नहीं रहता और यह वीरान पड़ा है। यहां पर बेहद कम लोग ही जाते हैं। इस जगह की सबसे पहले वेनिस के राजा ने यहां पर सैनिक अड्डा बनाया था। इसके बाद तुर्की के ऑटोमान साम्राज्य ने इस पर कब्जा कर लिया। हालांकि, साल 1904 में क्रीट के लोगों ने तुर्कों को यहां से खदेड़ दिया। इसके बाद यह आइलैंड को कोढ़ के मरीजों का अड्डा बना दिया गया। साल 1975 में दुनिया को इस कोढ़ आश्रम के बारे में पता चला। इसके बाद यूनानी सरकार की बहुत आलोचना हुई।

जिसके बाद यहां के सभी लोगों को इलाज के लिए ले जाया गया और इस कुष्ठ रोगी आश्रम को बंद कर दिया गया। इसके बाद से स्पिनालॉनगा आइलैंड वीरान पड़ा है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस आईलैंड पर कोढ़ के मरीजों के इलाज का भी कोई इंतजाम नहीं था। इस द्वीप पर एक ही डॉक्टर आता था, वो भी तब जब किसी मरीज को कोई और बीमारी हो जाती थी। इंद्र को बनाने से पहले ही कुष्ठ रोग का इलाज खोज लिया गया था लेकिन यहां रहने वाले मरीजों का इलाज नहीं होता था।

चार धाम यात्रा के लिए आईआरसीटीसी ने पेश किया शानदार टूर पैकेज, यात्रियों को मिलेंगी ये सुविधाएं

गर्मियों की छुट्टी में लो कहीं ना कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं। ऐसे में कई लोगों को परिवार के साथ चार धाम की यात्रा करने की इच्छा होती है। ऐसे लोगों के लिए भारतीय रेलवे चारों धामों की यात्रा के लिए एक खास ऑफर लेकर आई है। बता दें कि यात्रियों के लिए पावन धाम की यात्रा के ऐसे पैकेज भारतीय रेलवे की तरफ से समय-समय पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। आई जानते हैं आईआरसीटीसी के चार धाम टूर पैकेज के बारे में -

इतने दिनों का होगा टूर पैकेज

भारतीय रेलवे की ओर से यात्रियों को चार धाम की यात्रा के लिए एक स्पेशल टूर पैकेज दिया जा रहा है। आपको बता दें कि यह टूर पैकेज आजादी का अमृत महोत्सव और देखो अपना देश के तहत पेश किया गया है। इस पैकेज का नाम Char Dham Yatra E& Nagpur है। आईआरसीटीसी की ओर से जारी किया गया यह खास टूर पैकेज कुल 11 दिनों और 12 रातों का है। इच्छुक यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट irctctourism.com पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं।

इस दिन से शुरू होगी यात्रा और इन जगहों के होंगे दर्शन

रेलवे द्वारा यह चार धाम यात्रा 14 मई 2022 को नागपुर से शुरू होगी। यहां से यात्रियों को हवाई यात्रा के जरिए दिल्ली लाया जाएगा। दिल्ली से हरिद्वार के लिए ट्रेन रवाना होगी। इस टूर पैकेज के तहत यात्रियों को बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, गुप्तकाशी, बरकोट, जानकी चट्टी, सोनप्रयाग, उत्तरकाशी, आदि धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे।

यात्रियों को मिलेंगी ये सुविधाएं

यात्रा के दौरान यात्रियों को रेलवे की ओर बस और गाड़ी की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा प्रतिदिन नाश्ता और डिनर भी मिलेगा और ठहरने के लिए होटल की व्यवस्था भी करवाई जाएगी।

यात्रियों को देना होगा इतना शुल्क

अकेले यात्रा करने वाले यात्रियों को 77,600 रुपए देने होंगे। दो लोगों को इस रूप पैकेज के लिए 61,400 चुकाने होंगे। वहीं तीन लोगों को इस पैकेज के लिए 58,900 जमा करने होंगे। बता दें कि बच्चों का अलग से शुल्क पड़ेगा।

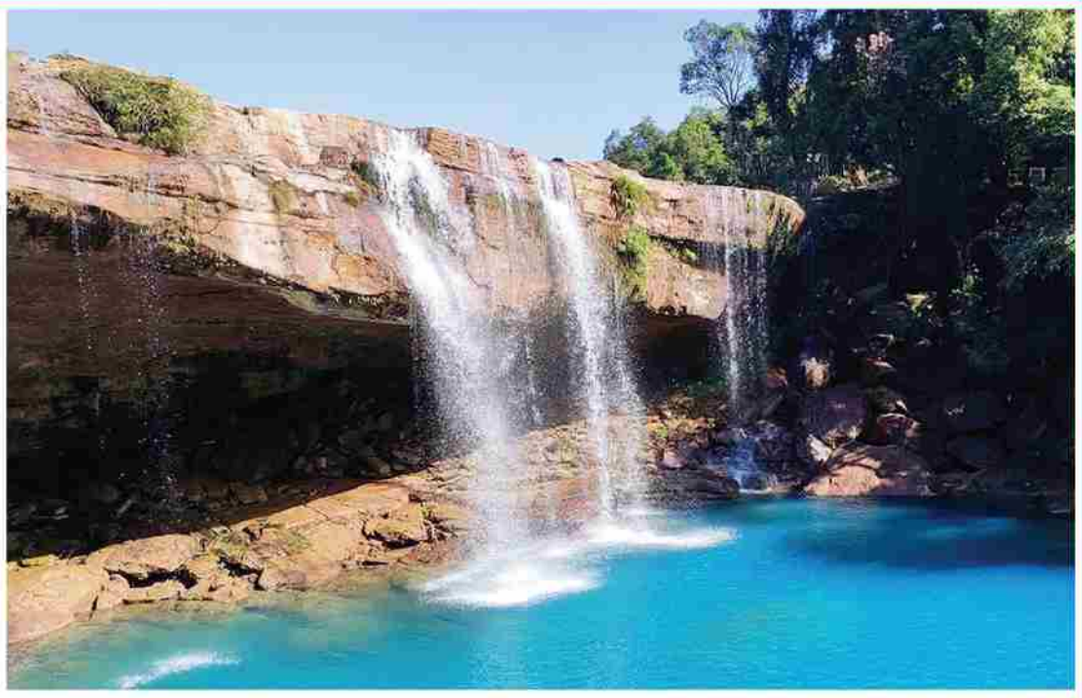

मेघालय राज्य की खूबसूरती देखेंगे तो बस देखते ही रह जायेंगे

1972 में असम से अलग होकर भारत के इक्कीसवें राज्य के रूप में नक्शे पर उभरा, अद्भुत नैसर्गिक सुषमा का आलय- मेघालय यानि बादलों का घर। आकाश में बादलों के झुंड, धरती पर चंचल झरने, शांत झीलें और उनमें अपना प्रतिबिम्ब निहारती हरियाली, इन सबके बीच आपकी उपस्थिति आपको अवसर देगी कि आप अपने भाग्य पर गर्व कर सकें। यह राज्य गारो, खासी तथा जयन्तिया जैसी प्राचीन पहाड़ी जनजातियों का मूल निवास स्थान है। इन्हीं लोगों को भारत का प्राचीनतम निवासी माना जाता है।

ब्रिटिश राज के दौरान स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट कहा जाने वाला शहर शिलांग मेघालय की राजधानी है। खासी पहाड़ियों में, समुद्रतल से लगभग 1500 मी. की ऊंचाई पर बसे इस शहर का नाम एक जनजातीय देवता शुलांग के नाम पर पड़ा है। प्यार से मिनी लंदन पुकारे जाने वाले शहर के चप्पे-चप्पे पर अंग्रेजी प्रभाव के निशान खोजे जा सकते हैं।

शिलांग जैसे छोटे शहर में दर्शनीय स्थानों की सूची छोटी नहीं है। शहर के बीचों-बीच स्थित है वार्डलेक। 1893-94 में बनी यह झील पर्यटकों का ही नहीं स्थानीय लोगों का भी प्रिय स्थान है। खूबसूरत बगीचों की हरियाली और झील के बीच में बना लकड़ी का पुल इसकी विशेषता है। इस लकड़ी के पुल पर से आप झील की मछलियों को देख सकते हैं और चाहें तो उन्हें आटे की गोलियां भी खिलाएं। नि:संदेह बच्चों को यह काम बहुत अच्छा लगेगा। झील के पानी में उतरना चाहें तो नौकाविहार कर सकते हैं। खाने-पीने का अच्छा प्रबंध होना इस स्थान को सुविधाजनक भी बना देता है।

यदि आपकी दिलचस्पी पेड़-पोधों में है तो झील के पास स्थित बाटेनिकल गार्डन अवश्य जाएं। वनस्पति विज्ञान के छात्रों के लिए यह स्थान बहुत उपयोग साबित होगा। इसके पास ही स्थित डेलिमार वांगखा का तितलियों का सग्रंह भी देखें। दुनिया भर का तितलियों से संबधित जिज्ञासा यहां शांत की जा सकती है।

किताबों में रूचि हो और ज्ञान में वृद्धि चाहें तो विशेष रूप से प्राचीन जीवन शैली से जुड़ी जानकारियों चाहें तो स्टेट सैन्ट्रल लाइब्रेरी जाना उचित होगा। साथ ही आपको अपनी ओर खीचेंगे डांन बास्को तथा आंल सैन्ट चर्च। डांन बास्को चर्च की विशाल इमारत और अनूठा प्रार्थना कक्ष ही इसकी खासियत हैं।

1889 में बना भारत का तीसरा सबसे पुराना गोल्फ कोर्स भी शिलांग में ही है। चीड़ और देवदार के ऊंचे वृक्षों से घिरे इस स्थान की मखमली धास का मजा लेने के लिए आपका गोल्फ में रूचि रखना जरूरी नहीं। अक्सर सूर्यादय और सूर्यास्त के सुन्दर दृश्यों को नजरों में भरनो के लिए भी पर्यटक यहां आते हैं।

खासी जनजाति के मातृ-सत्तात्मक समाज की छाप देंखें यहां के बड़ा बाजार में। इस बाजार को पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है। यहां खरीददारी करें हस्तशिल्प की और बांस के बने सामान की। यहां के जीवन को और करीब से जानना हो तो पास ही स्थित पुलिस बाजार भी जाना चाहिए।

शिलांग से लगभग 2 किलोमीटर दूर है एलिफेन्टा फॉल (झरना)। हाथी के आकार के इस प्राकृतिक झरने की सौन्दर्य वृद्धि की है लकड़ी के छोटे-छोटे पुलों ने। इस झरने के नाम के कारण के बारे में लोगों में मतैक्य नहीं है। कुछ लोगों के अनुसार इस जगह के नाम का कारण, कभी यहां हाथियों का पानी पीने आना था जबकि दूसरों के अनुसार, इसका हाथी जैसा आकार। कुछ लोग इसके नामकरण की कथा सुनाते हैं कि किसी अंग्रेज अधिकारी का हाथी रास्ता भटक कर यहां पहुंच गया और यहीं उसकी मृत्यु हो गई तो यह नाम पड़ा। इसी खींच-तान के बीच एक अन्य कथा यह भी है कि यहां हाथी पानी पीने आते थे। किसी कारण वश यहां एक हाथी की मृत्यू के पश्चात हाथियों ने यहां आना बंद कर दिया। स्थानीय लोग इस मृत हाथी को देखने यहां पहुंचे, यही घटना इस स्थान के नामकरण का कारण है। इसी से यह स्थान लोकप्रिय भी हुआ।

शिलांग और उसके आसपास के क्षेत्र में कई और झरने भी है जैसे मारग्रेट फांल, बिशप फांल, स्वीट फांल आदि।

समुद्र की सतह से लगभग 1960 मी. ऊंचाई पर, शिलांग से करीब 10 किमी. दूर है शिलांग पीक। ऐसा विश्वास है कि जनजातीय देवता शुलांग यहीं निवास करते हैं। यहां के खुले वातावरण और ऊंचाई को ध्यान में रखकर कुछ गर्म कपड़े ले जाना गलत नहीं होगा।

उमियाम झील, गुवाहाटी से शिलांग के बीच का सबसे सुन्दर पड़ाव है। यह स्थान शिलांग से लगभग 17 किमी. दूर है। बड़ा पानी के नाम से प्रसिद्ध यह झील एक बांध के निर्माण के फलस्वरूप अस्तित्व में आई थी। इस झील के पास बने नेहरू उद्यान को भी देखें। यह झील पानी के खेलों के लिए प्रसिद्ध है।

1897 के भयानक भूकंप से धरती पर तराशे गए दर्रे के लिए विख्यात है माफलोग। यहां प्रकृति की सुन्दरता ने भूकंप की भयावहता को ढक दिया है। शिलांग से लगभग 64 किमी दूर है जरकेम। यहां गधंक के झरने हैं। ऐसा विश्वास है कि झरनों के पानी से अनेक बीमारियों का निदान संभव है।

मेघालय की अन्य दो पहाड़ियां हैं गारो और जयन्तिया। गारो पहाड़ियों को जाना जाता है वनस्पतिक और वन्य जीवन की विविधता के लिए। यहां राष्ट्रीय वन्य जीवन उद्यान तथा नाफक झील भी देखें। यहां सिजु गुफाओं में चूने पत्थर की बनी आकृतियों को देखा जा सकता है।

हिलौरे लेती मिन्तदू नदी से घिरी जयन्तिया पहाड़ी शिलांग से लगभग 64 किमी. दूर हैं। जोवाई, जयन्तिया जनजाति का मुख्यालय भी यहीं है। यहां सिन्दाल गांव में अनेक गुफाओं की सैर की जा सकती है की। जयन्तियां राजा तथा विदेशी आक्रमणकारियों के बीच युद्ध के दौरान कभी इनका प्रयोग छिपने के स्थान के रूप में होता था।

लगभग 1300 मी की ऊंचाई पर, शिलांग से 56 किमी. दूर स्थित है चेरापूंजी। एक लंबे समय, इस क्षेत्र को विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता रहा है। यहां रोमांच लें विश्व के चौथे सबसे ऊंचे झरने नहिकालीफाई को देखने का। इसी प्रकार मांसमाई और लम लाबाध की रहस्यमयी गुफाओं की सैर भी यादगार साबित होगी।

वर्तमान में सर्वाधिक वर्षा तथा लगभग निरन्तर बने रहने वाले इन्द्रधनुषों की भूमि मांसेनरम, चेरापूंजी के पास ही है। वर्षा ऋतु में लगभग अगम्य बन जाने वाला यह स्थान अपने चूने पत्थर के बने विशाल शिवलिंग के लिए खासा लोकप्रिय है। यहां भयावह ऊंचाई लिए बेहत खूबसूरत झरने भी आपको भाएंगे।

जून-जुलाई का समय मेघालय में उत्सवों का समय है। 4 दिनों तक चलने वाला किसानों का उत्सव है वेटडीनक्लामू। इसमें पारम्परिक नृत्य संगीत के साथ-साथ बैलों की लड़ाई का मजा लें। स्थानीय देवता यू शिलांग और पूर्वजों के सम्मान में आयोजित होने वाले नौंग क्रेम नृत्य उत्सव में शामिल होना नहीं भूलें।

अधिक वर्षा वाले दिनों को छोड़ हर मौसम में यहां आया जा सकता है। यहां का जाड़ा कुछ अधिक ठंडा और गर्मियां सुहावनी होती हैं। निश्चय ही यह छोटा-सा राज्य गर्मी से बड़ी राहत दिला सकता है।

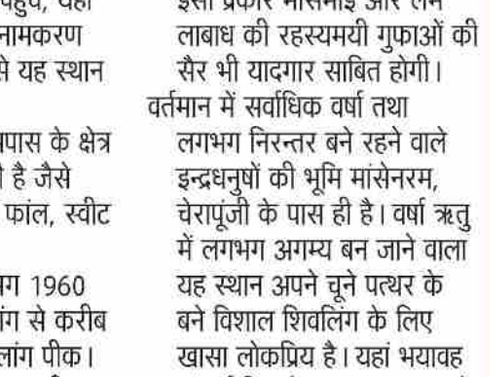

ये हैं अजमेर में घूमने की खूबसूरत जगहें, इन्हें नहीं देखा तो अधूरी है आपकी यात्रा

राजस्थान में अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ अजमेर शहर एक बहुत लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। यह शहर सूफी संत मोइउद्दिन चिश्ती की दरगाह के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है। अजमेर शहर को पहले 'अजयमेरु' के नाम से जाना जाता था। यह शहर अपनी विशिष्ट वास्तुकला और संस्कृति के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है। अजमेर में कई प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं जो देश-विदेश में बहुत प्रसिद्ध हैं। इस शहर में आपको पारंपरिक राजस्थानी रंग-ढंग देखने को मिलते हैं। आज के इस लेख में हम आपको अजमेर शहर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के बारे में बताने जा रहे हैं -

अजमेर शरीफ़

अजमेर में ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह यहाँ के सबसे प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। इस दरगाह में हर धर्म-जाति के लोग मत्था टेकने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर आगरा से 437 किमी। पैदल चलकर ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर बेटा होने की दुआ माँगने आए थे। आज के समय में देश-विदेश से लोग दरगाह पर आकर मन्नत मांगते हैं और मन्नत पुअर होने के बाद चादर चढ़ाते हैं।

आना सागर झील

अजमेर में आप आना सागर झील देख सकते हैं। यह एक बेहद खूबसूरत कृत्रिम झील है जो यहाँ आने वाले पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। इस झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पिता आणाजी चौहान ने करवाया था। आणाजी से नाम पर ही इस झील का नाम आना सागर पड़ा। इस झील के आसपास की जगह भी बेहद खूबसूरत है। यहाँ का दौलत बाग देखने में बहुत खूबसूरत है, जिसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। इस झील में आप नौका विहार का आनंद ले सकते हैं।

पुष्कर सरोवर

अजमेर स्थित पुष्कर झील देशभर में बहुत मशहूर है। यह सरोवर हिन्दू धर्म के लोगों के लिए आस्था का एक बड़ा केंद्र है। भारत के पांच पवित्र सरोवरों में पुष्कर झील भी शामिल है। कुछ विशेष अवसरों पर यहां श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए आते हैं। अजमेर आए पर्यटक पुष्कर सरोवर घूमने जरूर आते हैं। यहां आप ऊंट सवारी का आनंद ले सकते हैं।

अढ़ाई दिन का झोपड़ा

अजमेर में स्थित अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक ऐतिहासिक मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण 1192 में मोहम्मद ग़ोरी के निर्देश पर कुतुब-उद-दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था। इस मस्जिद में ढ़ाई दिन का उत्सव चलता है जिसकी वजह से इस मस्जिद को यह नाम दिया गया है। इस मस्जिद के निर्माण में खूबसूरत वास्तुकला का इस्तेमाल देखने को मिलता है। दूर-दूर से लोग इस मस्जिद में मत्था टेकने आते हैं।

तारागढ़ किला

तारागढ़ किला, अजमेर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है। इस किले का निर्माण सन 1354 में किया गया था और यह राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध प्राचीन संरचनाओं में से एक है। यह किला पर्यटकों के लिए राजस्थानी वास्तुकला का एक शानदार और उत्कृष्ट उदाहरण पेश करता है।

सोनी जी की नसियां

अजमेर में स्थित सोनी जी की नसियां एक प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं। इसे लाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर जैन धर्म के पहले तीर्थकर को समर्पित हैं। सोनी जी की नसियां मंदिर का मुख्य आकर्षण इसका मुख्य कक्ष है, जिसे स्वर्ण नगरी या सोने के शहर के नाम से भी जाना जाता हैं। इस मंदिर में जाएं धर्म से जुड़ी सोने की लकड़ी की कई आकृतियां बनी हुई हैं। यह मंदिर पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है और दूर-दूर से लोग इस मंदिर को देखने आते हैं।

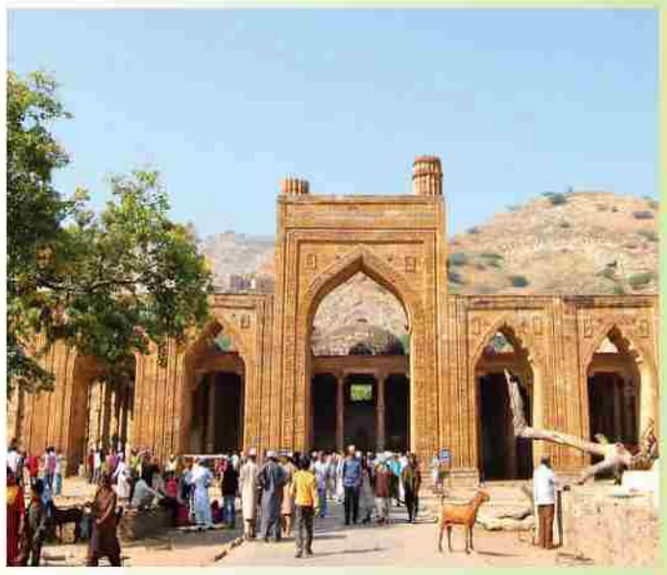

31 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार, ट्रेन में कपड़ों के बीच छिपाकर लाता था गांजा

नोएडा। थाना सेक्टर-63 पुलिस ने शातिर गांजा तस्कर गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से 31 किलो 400 ग्राम गांजा मिला है। इसकी कीमत करीब 3.25 लाख रुपए है। ये तस्करी स्कूटी से की जा रही थी। तस्कर की पहचान सनफराज निवासी चोटपुर, थाना

सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर के रूप में हुई है। इसे बहलोलपुर अंडरपास के पास सेक्टर-63 से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि ये शातिर किस्म गांजा तस्कर है। ये नोएडा में गांजा सप्लाई करता है। बिहार से गांजा यहां लेकर आता है। पूछताछ में बताया कि गांजा लेकर ये कपड़ों की पोटली बनाकर उसमे छिपा देता था। इसके बाद वहां से ट्रेन की जनरल बोगी में बैठकर दिल्ली या गाजियाबाद उतर कर नोएडा आता था। यहां डिमांड के मुताबिक गांजा सप्लाई करता था। पुलिस ने बताया कि ये किस-किस को गांजा देता था उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। बचा हुआ गांजा ये पुड़िया बनाकर बेच देता था।

नोएडा में लोहे की रॉड से युवक पर जानलेवा हमला, हालत गंभीर

नोएडा। थाना सेक्टर 113 क्षेत्र के सर्फाबाद गांव के पास स्थित एक कंपनी में काम करने वाले एक व्यक्ति के ऊपर लोहे की रॉड से एक अन्य व्यक्ति ने हमला कर दिया। इस घटना में उन्हें गंभीर चोट आई है। अत्यंत गंभीर हालत में उपचार के लिए उन्हें नोएडा के सेक्टर 50 स्थित नियो अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। वह वेंटिलेटर पर हैं। थाना सेक्टर 113 के प्रभारी निरीक्षक प्रमोद प्रजापति ने बताया कि सुंदर यादव पुत्र राम बाबू सर्फाबाद गांव के पास स्थित एक कंपनी में कार्यरत हैं। बीती रात को लालू यादव पुत्र राजेंद्र उनके पास आया। शराब के नशे में धुत लालू उनके साथ बदसलूकी करने लगा। जब उन्होंने विरोध किया तो लालू ने लोहे की रॉड से उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस घटना में उनके सिर और शरीर पर गंभीर चोट आई है। अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें नोएडा के सेक्टर 50 स्थित नियो अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि पीड़ित के बेटे की शिकायत पर पुलिस ने हत्या के प्रयास की धारा में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित के बेटे का कहना है कि उनके पिता की हालत अत्यंत नाजुक बनी हुई है। वह वेंटिलेटर पर हैं।

गाजियाबाद के स्वर्ण जयंती पार्क में चोरों का बोलबाला, 2 दिनों में लाखों की चोरी

गाजियाबाद। जिले के पॉश इलाके इंदिरापुरम स्थित स्वर्ण जयंती पार्क में आजकल चोरों का बोलबाला है। सरकारी सुरक्षाकर्मी पार्क से नदारद रहते हैं और चोर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पिछले 2 दिन में लाखों रुपए के बिजली के पोल और लोहे की ग्रिल जैसी चीजें चोरी हो गई है तो वही पार्क में उचित सुरक्षा ना होने के कारण महिलाएं भी पार्क में घूमने आने से कतराती हैं। गौरतलब है कि स्वर्ण जयंती पार्क में मौके पर चोरी हुए बिजली के खंभों को दिखाता हुआ ठेकेदार, मौके पर पुलिस की मौजूदगी चोरी हुए सामान की जांच पड़ताल में लगे हुए हैं लेकिन चोरों का कोई पता नहीं लगा। स्वर्ण जयंती पार्क में बिजली के इंपॉर्टेंट नारियल डिजाइन के कई कीमती खंबे चोरी हो गए, तो वही लव गार्डन में लगे हुए और पार्क के अन्य जगह पर लगे हुए लोहे के बिजली के पोल चोर खोलकर ले गए। यहां चोर बाकायदा पोल खोलने के लिए चाबी और अन्य सामान लाते हैं और तसल्ली के साथ खोल कर ले जाते हैं। पार्किंग से अक्सर गाड़ियां चोरी होती रहती है इतना ही नहीं बाथरूम मैं भी लगा पीतल, स्टील और प्लास्टिक का सामान चोरी कर लेते हैं तो पार्क के चारों तरफ लगी हुई ग्रिल भी उखाड़ कर ले जाते हैं। पिछले 1 सप्ताह में लाखों रुपए का सामान चोरी हो चुका है। जीडीए के सरकारी ठेकेदार ने पुलिस में इसकी शिकायत की है तो वही वहां घूमने आने वाले लोगों की भी शिकायत है कि सुरक्षा का उचित प्रबंध नहीं है। पार्क में असामाजिक तत्वों का आना जाना लगा रहता है।

मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश, दिल्ली में युद्ध स्तर पर करें हर घर को सीवर से कनेक्ट

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हर घर को सीवर कनेक्शन और यमुना सफाई परियोजना की समीक्षा बैठक की। इस दौरान केजरीवाल ने सख्त निर्देश दिए कि दिल्ली में एक घर भी सीवर कनेक्शन से वंचित न हो। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि ईस्ट दिल्ली में मार्च तक और नार्थ ईस्ट दिल्ली में जून 2023 तक 100 फीसद घरों को सीवर नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा।

हर घर सीवर कनेक्शन से यमुना को साफ करने में भी मदद मिलेगी। केजरीवाल ने कहा कि पूरी दिल्ली को सीवर नेटवर्क से जोड़ना हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है, ताकि यमुना में जरा भी गंदा पानी न गिरने पाए। उन्होंने कहा कि हर घर को सीवर कनेक्शन और यमुना सफाई परियोजना की अब हर 15 दिन में समीक्षा की जाएगी। समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज, मुख्य सचिव समेत दिल्ली जल बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

वहीं दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में कुल 1799 अनधिकृत कॉलोनियां हैं, जिनमें करीब 16 लाख 18 हजार 80 घर चिंहित किए गए हैं। इनमें से अभी तक 3 लाख 40 हजार 720 घरों को सीवर नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है और शेष पर काम चल रहा है। अधिकारियों ने बताया कि 747 कॉलोनियां पहले से ही सीवर नेटवर्क से कवर हैं। मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन

योजना के तहत 667 कॉलोनियों के 39 हजार 550 घरों में सीवर कनेक्शन दिया जा रहा है, जिनमें से 38 हजार 960 घरों को सीवर कनेक्शन दे दिया गया है और शेष घरों को मार्च तक सीवर कनेक्शन दे दिया जाएगा। 80 कालोनियों में प्रोजेक्ट डिविजन द्वारा सीवर कनेक्शन किए जा रहे हैं। यहां स्थित 98 हजार 665 घरों में से 46 हजार 498 घरों को सीवर कनेक्शन दे दिया गया है। शेष घरों को सितंबर 2023 तक कनेक्शन दे दिया जाएगा। 573 कालोनियों में सीवर नेटवर्क का काम चल रहा है। यहां स्थित 7 लाख 77 हजार 151 घरों में से 2 लाख 46 हजार 581 घरों को सीवर नेटवर्क से जोड़ दिया गया है और शेष घरों को दिसंबर 2023 तक सीवर नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। डीएसटीपी के अंतर्गत 318 कालोनियों के 4 लाख 45 हजार घरों को सीवर कनेक्शन दिया जाएगा। डीएसटीपी के लिए जमीन मिलने के 12 महीने के अंदर हर घर को सीवर नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा।

जबकि 161 कालोनियों में कई तकनीकी दिक्कतें हैं, जिनको दूर करने का प्रयास किया रहा है। अधिकारियों ने बताया कि दिसंबर 2023 तक 9 लाख 15 हजार 366 घरों को सीवर नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा और शेष घरों को अगले एक साल के अंदर सीवर नेटवर्क से जोड़ने की योजना है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों से पूछा कि पूर्वी दिल्ली में अभी तक जिन घरों तक सीवर कनेक्शन नहीं पहुंचा है, उन घरों को कब तक सीवर लाइन से जोड़ दिया जाएगा?

शिक्षा मंत्री को बिना जानकारी दिए एलजी ने सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल्स की नियुक्ति रोकी

नई दिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को दिल्ली सरकार के स्कूलों में प्रिंसिपलों की नियुक्ति पर उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना की टिप्पणी का खंडन करते हुए कहा कि एलजी ने शिक्षा मंत्री को दरकिनार कर प्रिंसिपलों की नियुक्ति रोक दी है और सरकार की ओर से देरी का दावा कर झूठ बोल रहे है।

एलजी ने ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मंत्री को रिपोर्ट न करें। सिसोदिया ने कहा कि एलजी 126 पदों को पुनर्जीवित करने का गलत तरीके से श्रेय लेकर दिल्ली के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि बाकी के 244 पदों को ठंडे बस्ते में डाल दिया हैं। एलजी को क्रेडिट लेना बंद करना चाहिए और उन्हें तुरंत 244 प्रिंसिपल्स की नियुक्ति को मंजूरी दे देनी चाहिए। उपमुख्यमंत्री ने तल्ख़ शब्दों में कहा कि, एलजी का दावा है कि उन्होंने शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के आधार पर 244 पदों को समाप्त करने की मंजूरी दी थी। क्या वह इस बात की

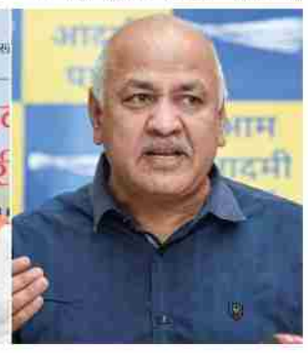

पुष्टि कर सकते हैं कि फाइल शिक्षा मंत्री के माध्यम से उनके पास भेजी गई थी ? क्या उन्होंने सर्विसेज से जुड़े मामलों पर मंत्री को जानकारी दिए बिना सीधे फाइल उनके पास रखने का अधिकारियों को निर्देश नहीं दिया है। इन 244 विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के पद तत्काल भरने की आवश्यकता है। उन्होंने अपील की है कि जब ये स्कूल पहले से ही कार्य कर रहे हैं तो इनमें प्रिंसिपलों की आवश्यकता है या नहीं इसकी स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें केवल एलजी से एक निर्णय की आवश्यकता है कि इन पदों के लिए स्टडी करने के बजाए इन सभी पदों को तुरंत भरना चाहिए।

एलजी केवल 126 पदों के रिवाइवल के लिए गलत तरीके से श्रेय लेकर दिल्ली के लोगों को गुमराह कर रहे हैं जबकि उन्होंने बाकी बचे 244 पदों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है।

दिल्ली के वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में 30 बच्चों को बाल श्रम से कराया मुक्त

नई दिल्ली। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन (केएससीएफ) के सहयोगी संगठन 'सहयोग केयर फॉर यू' ने श्रम विभाग, एसडीएम रामपुरा, डीसीपीसीआर और दिल्ली पुलिस के साथ मिल कर दिल्ली के वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में रेसक्यू ऑपरेशन कर 30 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया। रेसक्यू ऑपरेशन में बचाए गए सभी बच्चों की उम्र 13 से 17 साल के बीच की है। जिनमें से 4 लड़कियां हैं और बाकी सभी लड़के हैं। इन मासूम बच्चों को क्षेत्र में जूता बनाने की इकाइयों, होजरी इकाई, खिलौना निर्माण और स्टील के बर्तन बनाने वाली इकाइयों में बाल श्रमिकों के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया गया था। पूछताछ में बच्चों ने बताया कि उनसे प्रतिदिन 15 घंटे के लंबे समय तक काम कराया जाता था और उन्हें इसके बदले 150 रुपये से लेकर 250 रुपये तक की मामूली मजदूरी दी जाती थी। बच्चों से बेहद गंदी, असुरक्षित व अमानवीय परिस्थितियों में काम कराया जाता था, जहां हवा या

रोशनी का कोई रास्ता नहीं था। उन्हें अपना खाना भी खुद खरीदना पड़ता था। जिन बच्चों को बचाया गया उनमें से आधे बाल श्रमिकों की ट्रैफिकिंग पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के दूरदराज के इलाकों से की गई थी। सरस्वती विहार के एसडीएम के आदेश पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 370, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 और 79, चाइल्ड एंड अडॉलेसेंट लेबर एक्ट की 3, 14 और बॉंडेड लेबर सिस्टम एक्ट की धारा 16,17 और 18 के तहत एफआईआर दर्ज की है। सरस्वती विहार के एसडीएम ने पुलिस को निर्माण इकाइयों के दोषी मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू करने और बच्चों की न्यूनतम मजदूरी वसूलने आदेश दिया है। वहीं वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र से बाल श्रमिकों के रेसक्यू पर सहयोग केयर फॉर यू के महासचिव शेखर महाजन ने कहा, चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक ऐसा आपराधिक अवैध कारोबार है जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग और चाइल्ड एक्सप्लोइटेशन दिन प्रतिदिन दुनिया भर में बढ़ता ही जा रहा है।

हेमंत सोरेन ने अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात

नई दिल्ली। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। केजरीवाल ने मुलाकात की तस्वीर ट्विटर पर साझा करते हुए कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से दिल्ली में शिष्टाचार मुलाकात हुई और देश के विभिन्न मुद्दों पर सार्थक बातचीत हुई। करीब तीन साल पहले जनवरी 2020 में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब दिल्ली दौरे पर थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास पर जाकर उनसे मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात थी। हेमंत सोरेन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के संबंध में बातें की थी।

उन्होंने कहा था कि वे झारखंड में भी उसी तरह की योजनाओं को लागू करना चाहेंगे।

तब हेमंत सोरेन ने अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए अन्य विपक्षी दलों के नेताओं के साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी न्योता भेजा था। हालांकि अरविंद केजरीवाल शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने सांसद संजय सिंह को भेजा था। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में कांग्रेस गठबंधन सहयोगी की भूमिका में है।

दिल्ली-मेरठ मार्ग पर हुडदंग कर रहे 13 युवक गिरफ्तार, 2 गाड़ियां सीज

मोदीनगर। दिल्ली-मेरठ मार्ग पर लग्जरी गाड़ी सवार युवकों को हुडदंग करना काफी महंगा पड़ा। पुलिस ने हुड़दंग कर रहे 13 युवकों को गिरफ्तार कर उनकी गाड़ी सीज कर ली है।

पकड़े गए सभी युवक बुलन्दशहर के रहने वाले हैं और मोदीनगर में एक शादी में शामिल होने आए थे। दिल्ली-मेरठ मार्ग पर लग्जरी गाड़ी सवार युवक हुडदंग कर रहे थे। हुडदंग के चलते दिल्ली मेरठ मार्ग पर जाम जैसी स्थिति बन गई। किसी ने युवकों के हुड़दंग का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। जो वायरल हो गया। वीडियो वायरल होते ही मोदीनगर पुलिस सक्रिय हो गई। एसीपी रितेश त्रिपाठी ने सूचना मिलते ही पुलिस की कई टीमों को मौके पर भेजा। पुलिस ने काफी दूर तक पीछा कर राज चौपले के पास हुडदंग कर रहे युवकों को दबोच लिया और थाने ले आई। एसीपी रितेश त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस ने विनय, प्रदीप, सूरज,मनीष, दीपक, राधेश्याम, श्यामानंद, दीपक उर्फ

दीपू, छोटू, प्रवीण, जितेन्द्र, लव कुमार को गिरफ्तार कर शांतिभंग की धाराओं में चालान कर दिया है। उन्होने बताया कि दोनों गाड़ियों को सीज कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने एनडीएमसी के कर्मचारियों को नियमित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखा पत्र

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एनडीएमसी के कर्मचारियों को नियमित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। पत्र में मुख्यमंत्री ने लिखा कि ग्रुप सी भर्ती नियमों के शीघ्र अनुमोदन के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं, जिससे 4500 के करीब कर्मचारी एनडीएमसी में नियमित हो सकें। ग्रुप सी भर्ती नियमों के शीघ्र अनुमोदन के लिए प्रस्ताव कई बार भेजा गया। इसके बावजूद कर्मचारियों को नियमित करने की मांग अभी पूरी नहीं हुई है। स्थायी कर्मचारी न होने के कारण मामूली तनख्वाह में इनका घर चलाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में मानवता के आधार पर इन कर्मचारियों को स्थायी किया जाए।

केजरीवाल ने पत्र में कहा है कि मैंने 22 मार्च 2022 को आपसे अनुरोध किया था कि ग्रुप सी भर्ती नियमों के शीघ्र अनुमोदन के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं। जिससे आरएमआर

कर्मचारी (करीब 4500) एनडीएमसी में नियमित कर्मचारी बन सकें। इससे पहले ग्रुप सी भर्ती नियमों के शीघ्र अनुमोदन के लिए प्रस्ताव 25 सितंबर और 16 मार्च 2021 को भेजा गया था। इसके अलावा गृह मंत्रालय और एनडीएमसी के बीच हुए विभिन्न संचार-जवाब भी आपको 22 मार्च 2022 को भेजे गए थे। इसके बावजूद एनडीएमसी के इन टीएमआर और आरएमआर कर्मचारियों की नियमित करने की लंबे समय से लंबित शिकायत अभी तक दूर नहीं हुई है। उन्होंनेकहा कि एनडीएमसी ने 23 नवंबर 2022 को एक रिमाइंडर भी भेजा है, लेकिन ग्रुप सी के भर्ती नियमों के मसौदे की मंजूरी अभी तक गृह मंत्रालय द्वारा नहीं दी गई है। इसलिए मैं फिर से ग्रुप सी के मसौदा भर्ती नियमों के त्वरित अनुमोदन के मामले में आपके तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध करता हूं, ताकि इन आरएमआर कर्मचारियों की शिकायत को हल कर नियमित एनडीएमसी कर्मचारी बनाया जा सके। पिछले कुछ दिनों में कई बार एनडीएमसी में नियमित करने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री को कर्मचारियों ने अपनी परेशानियों से अवगत कराया था। कई सालों से अस्थायी कर्मचारी होने के चलते परिवार चलाने में आ रही कठिनाइयों के बारे में भी बताया था। अंत में केजरीवाल ने पत्र में भी लिखा कि यह काफी गरीब लोग हैं। इसमें से काफी लोग पिछले 20-25 साल से एनडीएमसी में नौकरी कर रहे हैं। स्थायी कर्मचारी न होने के कारण मामूली तनख्वाह में इनका घर चलाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में मानवता के आधार पर आपसे निवेदन है कि इन कर्मचारियों को स्थायी किया जाए। इससे पहले भी एनडीएमसी में अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया गया है। इस कारण भी इन कर्मचारियों को स्थायी करने में कोई वैधानिक समस्या नहीं आएगी। एनडीएमसी भी इस वक्त कर्मचारियों की कमी की समस्या से जूझ रहा है। इन कर्मचारियों के स्थायी होने से इस समस्या का समाधान भी हो जाएगा।

हज पर मिलने वाली सब्सिडी और 50 हजार रुपए की छूट केवल गुमराह करने का आदेश: अनीस मंसूरी

गाजियाबाद। मुस्लिम समुदाय की सबसे पुरानी संस्था पसमांदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी ने गाजियाबाद में एक प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली हज कमेटी और देश के प्रधानमंत्री को मुस्लिम समुदाय के सऊदी अरब जाने वाले हाजियों को मिलने वाली सब्सिडी खत्म करने और 50 हजार रुपए की छूट वाली खबर को एक गुमराह करने वाला आदेश बताया।

उन्होंने बीते दिनों लखनऊ में आयोजित हुई पसमांदा मुस्लिम समाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि पसमांदा मुस्लिम समाज ने प्रधानमंत्री को लेटर के तौर पर जो हाजियों को देने वाली सब्सिडी के बारे में बात की गई थी उसको नजरअंदाज करते हुए सिर्फ हाजियों को गुमराही और मुस्लिम समुदाय को गुमराह किया जा रहा है। अगर बात की जाए

पसमांदा मुस्लिम समाज की तो लगातार मुस्लिम अल्पसंख्यकों की आवाज को बुलंद करते हुए कई सालों से यह संस्था कार्य कर रही है। हालांकि बसपा और सपा कार्यकाल में अनीस मंसूरी को मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए मंत्री भी बनाया गया था। अब ऐसे में जब सत्ता हाथ से चली गई है और पसमांदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी मुस्लिमों की आवाज को उठाने के लिए लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिख रहे हैं। ऐसे में जहां एक तरफ केंद्र सरकार का कहना है कि मुस्लिम समुदाय को हज पर जाने के लिए फ्री वीजा और जो 50 हजार का सामान दिया जाता था, उसको खत्म कर दिया गया है। जिससे हाजियों के ऊपर यह दबाव होता था कि उनको यह सामान लेना जरूरी है वह अपने स्तर से अपने बजट के हिसाब से ला सकते हैं। वहीं अनीस मंसूरी ने इन्हीं बातों को दोहराते हुए बताया कि पसमांदा मुस्लिम समाज लगातार मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा हज कमेटी केंद्र मंत्रालय से हज सब्सिडी खत्म किए जाने का विरोध कर रहा है और मांग कर रहा है कि हज सब्सिडी दोबारा से दी जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा हज करने वाले लोग सऊदी अरब जा सके। वही टर्की और सीरिया में आए भूकंप से आहत मुस्लिम लोगों के लिए अपनी संवेदना प्रकट करते हुए अनीस मंसूरी ने गाजियाबाद से एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य जाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया। ऐसे में जब सत्ता हाथ में नहीं है तो पसमांदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस तरीके से बयान आना किसी हद तक विपक्ष में रहते हुए सरकार पर निशाना साधा है, और यही वजह है कि अनीस मंसूरी मुस्लिम समुदाय के ऊपर राजनीति करते हुए अपनी जमीनी राजनीति को एक वर्चस्व लेवल पर ले जाना चाहते हैं ताकि आने वाले समय में मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक में अपना कब्जा जमा सके।

एलिवेटेड रोड पर रील बनाने वाले 5 गिरफ्तार, गाड़ी सीज, लाइसेंस निरस्त की भेजी रिपोर्ट

गाजियाबाद। पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम ने एलिवेटिड रोड पर गाड़ी खड़ी कर मार्ग अवरुद्ध करते हुए, शराब पीते हुए हथियारों को लहराकर वीडियो बनाने वाले एवं हर्ष फायरिंग कर भय का माहौल पैदा करने वाले पांच अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से एक फॉर्चयूनर गाड़ी, 2 राइफल .315 बोर, 7 खोखा कारतूस व 1 जिन्दा कारतूस बरामद किया है। 5 फरवरी को थाना इंदिरापुरम क्षेत्रान्तर्गत एलिवेटिड रोड़ पर फॉर्चयूनर गाड़ी खड़ी कर मार्ग अवरुद्ध करते हुए शराब पीते हुए लोगों की जान को खतरे में डालकर हथियार लहराते हुए डांस करने का एक वीडियो एवं इसके पश्चात इन्ही अभियुक्तों द्वारा नीतिखण्ड-1 मे जाकर .315 बोर राइफल से हर्ष फायरिंग करने का एक दूसरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उक्त दोनों वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने से समाज मे भय का माहौल पैदा हुआ था।उक्त दोनों वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने 2 मामले दर्ज किए थे। दोनों मामलों में वीडियो के आधार पर जब जांच की गई अभियुक्त राजा चौधरी का नाम सामने आया। जिसको थाना इंदिरापुरम पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से फॉर्चयूनर गाड़ी बरामद की। गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर उसने अपने साथ पांच अन्य लोगो के संलिप्त होने की बात बताई। वीडियो मे हथियारो के विषय मे पूछताछ करने पर इसने बताया कि गाजियाबाद मे इसके दो जिम 24 फिटनेस रामलीला मैदान के सामने कविनगर व 24 फिटनेस चिरंजीव बिहार में है जिनकी सुरक्षा में गार्ड लगे हैं। जिनमें संतोष ठाकुर और अरुण चौहान शामिल हैं। इनके पास .315 बोर की राइफल है जिसको समाज मे धौंस बनाने के लिए यह अपने साथ ही लेकर चलता है। ये दोनो गार्ड वीआईपी सिक्योरिटी कम्पनी, गाजियाबाद के द्वारा इनके यहां मासिक वेतन पर नियुक्त किये गये हैं। राजा चौधरी से पूछताछ के आधार पर तत्काल पांच टीमो का गठन किया गया।

निराशा में डूबे कुछ लोग देश की प्रगति स्वीकार नहीं पर रहे : पीएम मोदी

नई दिल्ली, 08 फरवरी (एजेन्सी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि दुनिया में कोरोना महामारी सहित अनेक संकटपूर्ण हालात के बीच देश को जिस तरह से संभाला गया, उससे पूरा देश आत्मविश्वास से भर रहा है एवं पूरे विश्व में भारत को लेकर सकारात्मकता, आशा और भरोसा है। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए विपक्षी कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 तक का समय आजादी के इतिहास में सबसे अधिक घोटालों का दशक रहा है और संप्रग सरकार के इन दस साल के कार्यकाल में कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर कोने में भारत के लोग असुरक्षित महसूस करते थे।

मोदी ने 2जी, सीडब्ल्यूजी और अन्य घोटालों का जिक्र करते हुए कहा कि इन दस साल में वैश्विक मंचों पर भारत की साख इतनी कमजोर हो गयी थी कि दुनिया उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा कि दुनिया में सौ साल बाद कोरोना जैसी महामारी आई, विश्व बंटा हुआ है, ऐसी स्थिति में भी राजग सरकार के कार्यकाल में देश को जिस तरह से संभाला गया, उससे पूरा देश आत्मविश्वास से भर रहा है एवं पूरे विश्व में भारत को लेकर सकारात्मकता, आशा और भरोसा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि संप्रग सरकार के दस साल का कार्यकाल जहां लॉस्ट डिकेड था, वहीं 2030 तक का दशक इंडियाज डिकेड होगा। उन्होंने कहा कि आज जब कई देशों में भीषण महंगाई, बेरोजगारी, खानेपीने का संकट है और अपने पड़ोस में भी ऐसे हालात हैं, ऐसी स्थिति में कौन हिंदुस्तानी इस बात पर गर्व नहीं करेगा कि ऐसे समय में भी देश दुनिया की पांचवीं अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि आज राष्ट्र के रूप में गौरव पूर्ण अवसर हमारे सामने हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के पूरे अभिभाषण में जो बातें कही गयी हैं वे 140 करोड़ देशवासियों के लिए उत्सव का अवसर हैं।

मोदी ने कहा कि खुशी की बात है कि आज भारत को विश्व के समृद्ध देशों के समूह जी-20 की अध्यक्षता का अवसर भी मिला, जो देश के लिए गर्व की बात है। कांग्रेस सदस्यों की टीका-टिप्पणी के बीच प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों को इसका भी दुख हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के सारे विशेषज्ञों को भारत से बहुत आशा और विश्वास है, जिसका कारण भारत में आई स्थिरता, उसकी वैश्विक साख, बढ़ता सामर्थ्य और नयी संभावनाएं हैं।

प्रधानमंत्री के जवाब के दौरान सदन में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे। मोदी ने कहा कि देश में आज स्थिर और निर्णायक सरकार है जिसका भरोसा होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि यह सरकार पूर्ण बहुमत से चलती है और राष्ट्रहित में फैसले लेने का सामर्थ्य रखती है। उन्होंने कहा, हम इस मार्ग से हटने वाले नहीं, इस पर चलते रहेंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि चर्चा में सभी सदस्यों ने अपनी रुचि, प्रवृत्ति और प्रकृति के अनुसार सबने अपनी बातें रखीं। उन्होंने कहा कि जब हम इन बातों को गौर से सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं तो समझ में आता है कि किसकी कितनी क्षमता है, किसकी कितनी योग्यता है, किसकी कितनी समझ है और किसका क्या इरादा है। मोदी ने कहा कि देश भलीभांति इन बातों का मूल्यांकन करता है।

उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए एक शेर पढ़ा और कहा कि ऐसे लोगों के लिए कहा गया है, ये कह-कहकर हम दिल को बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं।

मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में संकल्प से सिद्धि तक का बढ़िया तरीके से खाका खींचा गया जिसमें एक प्रकार से देश को लेखाजोखा भी दिया गया और प्रेरणा भी दी गयी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, कुछ लोगों ने अभिभाषण से कन्नी काटी। एक बड़े नेता तो राष्ट्रपति का अपमान कर चुके हैं। जनजातीय समुदाय के प्रति उनकी सोच क्या है, यह सामने आ गया।

माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री का इशारा कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की तरफ था जिन्होंने कुछ महीने पहले राष्ट्रपति के खिलाफ एक टिप्पणी की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहुत सारी बातों को विपक्ष ने भी मौन रहकर स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि चर्चा में किसी सदस्य ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में भारत के दुनिया की समस्याओं के समाधान बनने, इस सरकार में लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिलने, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलने तथा नीतिगत पंगुता से उबरने जैसे उल्लेखों का विरोध नहीं किया। मोदी ने कहा, मुझे आशंका थी कि कुछ लोग इन बातों का विरोध करेंगे, लेकिन मुझे खुशी है कि किसी ने विरोध नहीं किया।

लोकसभा में अदाणी मुद्दे पर कुछ नहीं बोले पीएम, राहुल का तंज- मित्र को बचा रहे पीएम

नई दिल्ली, 08 फरवरी (एजेन्सी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। हालांकि इस दौरान अदाणी को लेकर लगाए जा रहे विपक्ष के आरोपों पर पीएम ने कुछ नहीं कहा। इसे लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सदन के बाहर पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन पर पलटवार किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर अदाणी को बचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम ने एक भी जवाब नहीं दिया। उनके भाषण से सच्चाई दिखती है। अगर (अदाणी) मित्र नहीं है तो उनको कहना चाहिए था कि जांच कराएंगे।

लोकसभा में प्रधानमंत्री के भाषण के बाद सदन के बाहर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मैं संतुष्ट नहीं हूं।

पीएम के संबोधन में अदाणी मामले का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री के संबोधन में सच्चाई दिखती है। उन्होंने एक भी जवाब नहीं दिया। जांच कराने की बात नहीं की। अगर मित्र नहीं हैं तो कहते ठीक है मैं जांच कराउंगा, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा।

राहुल गांधी ने आगे जवाब देते हुए कहा कि उनका (अदाणी) शेल कंपनी, डिफेंस इंडस्ट्री में बहुत बेनामी पैसा घूम रहा है। उस पर प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। इससे साफ है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था कि जांच कराएंगे। बहुत बड़ा घपला है। जरूर उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं मैं समझता हूं ऐसा क्यों है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पर जवाब दिया। उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं देख रहा था कल। कुछ लोगों के भाषण के बाद उनके समर्थक उछल रहे थे। वे खुश होकर कहने लगे कि ये हुई ना बात। शायद नींद भी अच्छी आई होगी। शायद आज उठ भी नहीं पाए होंगे। ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छे ढंग से कहा गया है- ये कह कहकर हम दिल को बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं।

आरबीआई ने लगातार छठी बार बढ़ाया रेपो रेट, लोन होंगे महंगे

नई दिल्ली, 08 फरवरी (एजेन्सी)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने बुधवार को रेपो दर को 25 आधार अंकों से बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत कर दिया। बुधवार को एमपीसी की बैठक इस वित्त वर्ष की आखिरी बैठक थी।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने महंगाई को लक्ष्य के अनुरूप दायरे में लाने के उद्देश्य से बुधवार को चालू वित्त वर्ष की आखिरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में एक बार फिर नीतिगत दर रेपो में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि की। इससे मुख्य नीतिगत दर बढ़कर 6.50 प्रतिशत हो गई है।

रेपो दर में वृद्धि का मतलब है कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिया जाने वाला कर्ज महंगा होगा और मौजूदा ऋण की मासिक किस्त (ईएमआई) बढ़ेगी।

आरबीआई ने मुख्य मुद्रास्फीति (मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र की महंगाई) ऊंची रहने की भी बात कही है। इसके साथ आने वाले समय में नीतिगत दर रेपो में और वृद्धि का संकेत दिया है।

केंद्रीय बैंक ने अगले वित्त वर्ष में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान रखा है। यह चालू वित्त वर्ष के सात प्रतिशत के वृद्धि दर के अनुमान से कम है।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की सोमवार से शुरू हुई तीन दिन की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, मौजूदा आर्थिक स्थिति पर विचार करते हुए एमपीसी ने नीतिगत दर रेपो को 0.25 प्रतिशत बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत करने का निर्णय किया है।

मौद्रिक नीति समिति के छह सदस्यों में से चार ने रेपो दर बढ़ाने और उदार रुख को वापस लेने पर ध्यान देने के पक्ष में मतदान किया।

हालांकि, रेपो दर में वृद्धि की यह गति पिछली पांच बार की वृद्धि के मुकाबले कम है और बाजार इसकी उम्मीद कर रहा था।

रेपो दर वह ब्याज दर है, जिसपर वाणिज्यिक बैंक अपनी फौरी जरूरतों को पूरा करने के लिये केंद्रीय बैंक से कर्ज लेते हैं।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की सोमवार से शुरू हुई तीन दिन की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, मौजूदा आर्थिक स्थिति पर विचार करते हुए एमपीसी ने नीतिगत दर रेपो 0.25 प्रतिशत बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत करने का निर्णय किया है।

आरबीआई मुख्य रूप से मुद्रास्फीति को काबू में लाने के लिये इस साल मई से लेकर अबतक कुल छह बार में रेपो दर में 2.50 प्रतिशत की वृद्धि कर चुका है। इससे पहले, मई में रेपो दर 0.40 प्रतिशत तथा जून, अगस्त तथा सितंबर में 0.50-0.50 प्रतिशत तथा दिसंबर में 0.35 प्रतिशत बढ़ायी गयी थी।

आर्थिक वृद्धि के बारे में दास ने कहा, वैश्विक स्तर पर उतार-चढ़ाव के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष में तीसरी और चौथी तिमाही के आंकड़े बताते हैं कि भारत की स्थिति मजबूत बनी हुई है। सोच-समझकर किये जाने वाले खर्च में सुधार के साथ शहरों में खपत मांग मजबूत हुई है। खासकर यात्रा, पर्यटन और होटल जैसे सेवा क्षेत्र में यह देखा जा रहा है।

उन्होंने कहा, गांवों में मांग में सुधार के संकेत बने हुए हैं। दिसंबर में दोपहिया और ट्रैक्टर की बिक्री बढ़ी है।

दास ने कहा कि, इन सब चीजों को देखते हुए 2023-24 में स्थिर मूल्य पर जीडीपी वृद्धि दर 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 6.2 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में छह प्रतिशत और चौथी तिमाही में 5.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

मुद्रास्फीति के बारे में आरबीआई गवर्नर ने कहा, महंगाई में कमी के संकेत हैं लेकिन मुख्य मुद्रास्फीति ऊंची बनी हुई है और यह चिंता की बात है। हमें खुदरा मुख्य मुद्रास्फीति को नीचे लाने के लिये प्रतिबद्ध रहना होगा।

उन्होंने कहा कि आयातित मुद्रास्फीति में कमी की उम्मीद के साथ अगले वित्त वर्ष 2023-24 में खुदरा महंगाई दर नरम पड़कर 5.3 प्रतिशत पर आने का अनुमान है।

उन्होंने कहा, वित्त वर्ष 2023-24 में मुद्रास्फीति नीचे आएगी। हालांकि, यह चार प्रतिशत से ऊपर रहेगी। मुद्रास्फीति का परिदृश्य भू-राजनीतिक तनाव की वजह से पैदा हुई अनिश्चितताओं, वैश्विक वित्तीय बाजार में उतार-चढ़ाव, गैर-तेल जिंसों की कीमतों में तेजी और कच्चे तेल की कीमतों के उतार-चढ़ाव से प्रभावित होगा।

आरबीआई को खुदरा मुद्रास्फीति दो प्रतिशत घट-बढ़ के साथ चार प्रतिशत पर रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है।

दास ने कहा, भारत की कच्चे तेल की खरीद औसतन 95 डॉलर प्रति बैरल रहने के अनुमान के आधार पर 2022-23 में मुद्रास्फीति के 6.5 प्रतिशत रहने की संभावना है।

उन्होंने कहा, मानसून सामान्य रहने पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 2023-24 में 5.3 प्रतिशत रहेगी। पहली तिमाही में यह पांच प्रतिशत, दूसरी में 5.4 प्रतिशत, तीसरी में 5.4 प्रतिशत और चौथी तिमाही में यह 5.6 प्रतिशत रहेगी। महंगाई को लेकर जोखिम दोनों तरफ बराबर है।

चालू खाते के घाटे (कैड) के बारे में आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कैड में 2022-23 की दूसरी छमाही में कमी आने का अनुमान है। कैड 2022-23 की पहली छमाही में जीडीपी का 3.3 प्रतिशत रहा जो 2021-22 की इसी अवधि में 0.2 प्रतिशत था।

उन्होंने कहा, वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही में स्थिति में सुधार हुआ है। जिंसों के दाम में कमी के साथ आयात कुछ कम हुआ है। इससे व्यपार घाटा कम हो रहा है।

रुपये के बारे में दास ने कहा कि एशिया की अन्य मुद्राओं की तुलना में घरेलू मुद्रा में अभी भी कम उतार-चढ़ाव है। रुपये में जो हाल में उतार-चढ़ाव आया है, वह वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान आई गिरावट से काफी कम है।

दास ने विकासात्मक और नियामकीय नीतियों के तहत कहा कि कर्ज पर जुर्माने को लेकर बैंकों की अलग-अलग नीतियां हैं। इस मामले में पारदर्शिता लाने और ग्राहकों के हितों के संरक्षण को लेकर जुर्माना लगाये जाने के बारे में विभिन्न पक्षों से राय लेने को लेकर दिशानिर्देश का मसौदा जारी किया जाएगा।

आरबीआई ने भारत आने वाले यात्रियों को व्यापारियों या दुकानदारों (पी 2 एम) को भुगतान के लिए भी यूपीआई सुविधा देने का प्रस्ताव किया है। शुरुआत में यह सुविधा जी-20 देशों के यात्रियों को मिलेगी।

इसके अलावा केंद्रीय बैंक 12 शहरों में क्यूआर कोड-आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन (क्यूसीवीएम) पर एक पायलट परियोजना भी शुरू करेगा। इससे सिक्कों की उपलब्धता बढ़ेगी।

एमपीसी की अगले वित्त वर्ष की पहली बैठक तीन से छह अप्रैल को होगी।

आप कितना भी गुमराह कर लें, देश मोदी के साथ है : किरेन रिजिजू

नई दिल्ली, 08 फरवरी (एजेन्सी)। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोच और समर्पण का भाव गंगा नदी की तरह 'पवित्र' है। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि विपक्ष कितना गुमराह कर ले, लेकिन देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ है।

कानून मंत्री रिजिजू ने कहा कि अफसोस की बात है कि कांग्रेस के नेता और कुछ सदस्यों ने ऐसी बातों का जिक्र किया जिसका अभिभाषण से कोई लेनादेना नहीं है। उनका कहना था, सदन नियम से चलता है और इसकी एक परंपरा है। राहुल गांधी 2004 से इस सदन में हैं। उम्मीद कर रहा था कि राहुल जी अनुभवी होंगे, बहुत कुछ सीखें होंगे...जब सदन का दुरुपयोग होता है तो दुख होता है।

राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, यात्रा करने के बाद अच्छी बातें बतानी चाहिए थी। नकारात्मक बातें की गईं जिससे देश और सदन का कोई लाभ नहीं होगा। केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा, इसमें कोई मतभेद नहीं है कि 2014 तक रोजाना घोटाले और भ्रष्टाचार की बात सामने आती थी। लोगों का नेताओं और सरकार पर विश्वास कम हो गया था। नरेन्द्र मोदी जी ने यह विश्वास फिर से कायम किया है। उन्होंने कहा, जैसे गंगा नदी पवित्र है, प्रधानमंत्री जी की सोच और समर्पण भाव उसी तरह पवित्र है।

रिजिजू ने कहा, पिछले लोकसभा चुनाव में चौकीदार चोर है का नारा दिया गया तो जनता ने करारा जवाब दिया। मुझे लगा कि वह सीख लेंगे। फिर उससे बड़ी गलती कर रहे हैं। जनता पहले से भी ज्यादा बड़ा जवाब देगी। उन्होंने कहा, सदन में झूठ बोलने के लिए राहुल गांधी जी पर किसने दबाव बनाया? देश को समस्या नहीं है, समस्या इनको है।

मंत्री ने राहुल के एक बयान पर पलटवार करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी देश के काम के लिए विदेश जाते हैं। वह छुट्टियां मनाने नहीं जाते। हम जानते हैं कि राहुल गांधी किस लिए विदेश जाते हैं। उन्होंने दावा किया, पाकिस्तान की भाषा और कांग्रेस की भाषा में हमेशा क्यों तालमेल होता है? आप ऐसी भाषा क्यों बोलते हैं जिससे देश को नुकसान होता है। सदन में राहुल गांधी द्वारा एक तस्वीर दिखाये जाने के जवाब में रिजिजू ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गौतम अडाणी के साथ एक तस्वीर भी सदन में दिखाई।

अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ महबूबा का प्रदर्शन, हिरासत में लिया गया

नई दिल्ली, 08 फरवरी (एजेन्सी)। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू-कश्मीर प्रशासन के अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती को हिरासत में ले लिया।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कई वीडियो में पुलिस को महबूबा मुफ्ती को प्रदर्शन स्थल से उठाकर पास की एक पुलिस वैन में ले जाते हुए दिखाया गया है।

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की नेता ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर प्रशासन की 'बुलडोजर नीति' के विरोध में रेलवे भवन से संसद तक मार्च करने की योजना बनाई थी।

पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने से पहले उन्होंने कहा, 'जम्मू और कश्मीर को अफगानिस्तान जैसी जगह में बदला जा रहा है।'

पुलिस ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती को जम्मू-कश्मीर में चल रहे अतिक्रमण रोधी अभियान के विरोध में बुधवार को यहां संसद तक मार्च निकालने से रोक दिया।

पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ महबूबा ने रेलवे भवन से संसद तक मार्च करने की योजना बनाई थी, जहां वह जम्मू-कश्मीर प्रशासन की बुलडोजर नीति के बारे में विपक्षी दलों को सूचित करना चाहती थीं।

हालांकि, पुलिस ने जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री को हिरासत में ले लिया और उन्हें तथा उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जंतर-मंतर ले गई।

महबूबा ने कहा, हम लोगों, विपक्षों दलों और सत्तारूढ़ भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) के सदस्यों को जम्मू-कश्मीर के लोगों की परेशानियों के बारे में बताने आए थे।

उन्होंने सवाल किया, अगर हम संसद नहीं जा सकते, तो हम कहा जाएं। क्या सरकार चाहती है कि हम अपनी शिकायतें लेकर संयुक्त राष्ट्र जाएं?

महबूबा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में कानून का शासन नहीं है और हम अपने दिल की बात कहने के लिए दिल्ली आए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि यहां भी आम जनता की आवाज दबा दी गई।

पीडीपी और जम्मू-कश्मीर के अन्य राजनीतिक दलों ने अतिक्रमण रोधी अभियान की निंदा की है और प्रशासन से इसे रोकने को कहा है। उनका कहना है कि इसका असर गरीबों पर पड़ रहा है।

मानस की कुछ चौपाइयों को हिंदू धर्म से जोड़कर भटका रहे कुछ लोग : स्वामी प्रसाद

लखनऊ, 08 फरवरी (एजेन्सी)। रामचरितमानस को लेकर राजनीतिक विवाद खड़े करने वाले सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य चुप होने का नाम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मानस की कुछ चौपाइयों को संशोधित व प्रतिबंधित करने की मांग को, कुछ लोग श्रीराम, हिंदू धर्म और रामचरितमानस से जोड़कर मामले को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं।

स्वामी प्रसाद ने मौर्य ने बुधवार को ट्विटर के माध्यम से लिखा कि मानस की आपत्तिजनक कुछ चौपाइयों को संशोधित व प्रतिबंधित करने की मांग को, कुछ लोग श्रीराम, हिंदू धर्म और रामचरितमानस से जोड़कर मामले को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही लोग महिलाओं, आदिवासियों, दलितों व पिछड़ों के 97 फीसद आबादी के सम्मान के विरोधी हैं। इससे पहले उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री आप चुनाव के समय इन्हीं महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ो को हिंदू कहते हैं। आरएसएस प्रमुख, मोहन भागवत कहते हैं कि जाति पंडितों ने बनाई तो आखिर इन्हें नीच, अधम, प्रताड़ित, अपमानित करने वाली रामचरितमानस की आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटाने हेतु पहल क्यों नहीं।

उन्होंने कहा कि यदि यह बयान मजबूरी का नहीं है तो साहस दिखाते हुए केंद्र सरकार को कहकर, रामचरितमानस से जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर नीच, अधम कहने तथा महिलाओं, आदिवासियों, दलितों व पिछड़ों को प्रताड़ित, अपमानित करने वाली टिप्पणियों को हटवायें। मात्र बयान देकर लीपापोती करने से बात बनने वाली नहीं है।

डियर साप्ताहिक लॉटरी
कोलकाता निवासी ने
₹ 1 करोड़ जीते

साप्ताहिक लॉटरी के ड्रॉ में प्रथम पुरस्कार के तौर पर रु. 1 करोड़ जीते हैं। उनकी विजेता टिकट का नंबर **80C 30002** है। उन्होंने नागालैंड स्टेट लॉटरीज के पास प्राइज क्लेम फॉर्म के साथ अपनी पुरस्कार-विजेता टिकट जमा कर दी है। "एक गृहिणी होने के तौर पर मैं अपनी किस्मत आजमाने हेतु नियमित तौर पर तुरंत डियर लॉटरी टिकटें खरीद लेती हूं। मैंने अपने दोस्तों एवं परिवार के सदस्यों को भी डियर लॉटरी खरीद कर अपनी किस्मत आजमाने की सलाह दी है। इसमें हमें ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ते हैं। हम इसे अपने मामूली खर्चों के तहत ही खरीद सकते हैं।" विजेता ने कहा। डियर लॉटरी के ड्रॉ लाइव दिखाये जाते हैं।

कोलकाता, पश्चिम बंगाल की श्रीमती श्रेकांता बागरी ने **08.12.2022** को सम्पन्न हुए डियर

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक : सत्येन्द्र नाथ सिंह एवं मुद्रक: नूतन वर्मा द्वारा प्राइम प्रिंटर्स, प्रिमुला कॉटेज, चर्च रोड, गंगटोक से मुद्रित एवं रतना निवास, मेट्रो प्वाइंट, नेशनल हाईवे 10, गंगटोक (पूर्व सिक्किम) से प्रकाशित।
सम्पादक - सत्येन्द्र नाथ सिंह, कार्यकारी सम्पादक - अश्विनी आनंद, मोबाइल नं. : 9474355832, 9609024017, फोन नं. : 03592-204174, पोस्टल रजि. सं. : WB/SKM/110/07-09, e-mail ID : anugamini@gmail.com

सिक्किमी जनता के प्रति हार्दिक धन्यवाद

युगों से सिक्किमी नेपाली समुदाय पर लगे विदेशी के कलंक को सदा के लिए मिटाने में आप – हम इस बार सक्षम बने। इस विकट, संघर्षपूर्ण और संवेदनशील समय में भी सरकार के साथ, सहयोग और विश्वास कर इस मुद्दे के समाधान के लिए एकजुट हुए सम्पूर्ण सिक्किमी जनता के प्रति मैं हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूं। आपकी ही एकता, अटूट साथ और सहयोग के कारण छोटी अवधि में ही हम सिक्किमी जनता पर अनावश्यक रूप से आए संकट को हटा सके। इस ऐतिहासिक क्षण में इसका सम्पूर्ण श्रेय सिक्किमी जनता को देते हुए एक बार पुनः मैं सिक्किमी जनता को बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद ज्ञापन करता हूं।

धन्यवाद आपका ईमानदार सेवक,

प्रेम सिंह तमांग (गोले)
मुख्यमंत्री, सिक्किम